राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

स्वतंत्र प्रभात

जो लिखेगा, वही टिकेगा

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. (UHIN/2009/34814) (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, बुधवार , 21 जनवरी 2026

वर्ष 16, अंक 72, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

राशन के साथ कोटेदार जबरन थमा रहे हैं घटिया सामान ..03

ऐसे आयोजनों से बढ़ता है आपसी सौहार्द- एडीएम..04

धारा 17-A पर क्यों बंटा सुप्रीम कोर्ट, क्या इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ कमजोर हो रही लड़ाई? समझें हर पहलू

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

भ्रष्टाचार किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है. यह केवल आर्थिक नुकसान नहीं करता, बल्कि जनता का भरोसा, शासन की विश्वसनीयता और न्याय व्यवस्था की आत्मा को भी कमजोर करता है. भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988. इस कानून का उद्देश्य साफ है- सरकारी पदों पर बैठे लोगों को जवाबदेह बनाना और जनता के पैसे तथा अधिकारों की रक्षा करना. लेकिन समय-समय पर इस कानून में ऐसे संशोधन किए गए, जिन पर यह सवाल उठने लगे कि क्या ये वास्तव में भ्रष्टाचार रोकने के लिए हैं या फिर भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए. साल 2018 में इसी कानून में जोड़ी गई धारा 17- A ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी. यही धारा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में विवाद का केंद्र बन गई है।

धारा 17- A क्या है, जिस पर है विवाद?

धारा 17-Aके अनुसार, यदि किसी सरकारी अधिकारी पर यह आरोप है कि उसने अपने आधिकारिक पद पर कोई निर्णय या सिफारिश करते समय भ्रष्टाचार किया है, तो उसके खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होगा. सरल शब्दों में कहें तो, पुलिस या जांच एजेंसी किसी अधिकारी के खिलाफ सीधे जांच शुरू नहीं कर सकती, जब तक सरकार हरी झंडी न दे. हालांकि, रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़े जाने जैसे मामलों में यह शर्त लागू नहीं होती. यहीं से विवाद शुरू होता है, क्योंकि सवाल उठता है कि जब जांच सरकार के ही अधिकारियों या मंत्रियों से जुड़ी हो, तो क्या सरकार निष्पक्ष रूप से अनुमति दे पाएगी?

जनहित याचिका और उसका उद्देश्य

सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम की गैर-लाभकारी संस्था ने इस धारा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. उनका कहना था कि यह प्रावधान संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करता है. इस याचिका का उद्देश्य केवल एक कानून को चुनौती देना नहीं था, बल्कि यह तय करना था कि भारत में भ्रष्टाचार की जांच कितनी स्वतंत्र और कितनी निष्पक्ष होगी।

संविधान से जुड़ा सवाल

इस मामले में मुख्य रूप से संविधान के दो अनुच्छेदों का जिक्र हुआ है. अनुच्छेद 14, जो समानता का अधिकार देता है और अनुच्छेद 21, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है. याचिकाकर्ता का कहना था कि धारा 17 इन दोनों अधिकारों का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह कानून के सामने सभी को बराबर नहीं मानती और न्याय तक पहुंच में बाधा डालती है. याचिकाकर्ता ने बताया कि इससे पहले दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में भी ऐसा ही प्रावधान था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था. अदालत ने तब कहा था कि जांच पर कार्यपालिका का नियंत्रण लोकतंत्र के लिए खतरनाक है. अब वही व्यवस्था नए नाम और नए कानून के जरिए वापस लाई गई है, जो अदालत के पुराने फैसलों का अपमान है।

जांच की स्वतंत्रता पर सीधा हमला

जांच एजेंसियों की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्वतंत्रता होती है. अगर जांच शुरू करने के लिए भी सरकार से अनुमति लेनी पड़े, तो जांच एजेंसियां केवल नाम की स्वतंत्र रह जाएंगी. याचिकाकर्ता ने कहा कि यह व्यवस्था पुलिस और जांच एजेंसियों को सरकार के अधीन बना देती है. भ्रष्टाचार अक्सर नीतिगत फैसलों में ही होता है. टेंडर, ठेके, लाइसेंस, परियोजनाएं और अनुमति, यही वे क्षेत्र हैं जहां बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होता है. यदि इन्हीं फैसलों को जांच से बाहर कर दिया जाए, तो भ्रष्टाचार कानून का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा।

देरी से न्याय को पहुंच सकता है नुकसान

भ्रष्टाचार के मामलों में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है. फाइलें बदली जा सकती हैं, दस्तावेज गायब हो सकते हैं और गवाहों पर दबाव डाला जा सकता है. यदि जांच शुरू होने में ही महीनों लग जाएं, तो सच्चाई सामने आना लगभग असंभव हो जाता है. इस कानून से ईमानदार अधिकारी, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता सभी डर जाएंगे. कोई भी सरकार के खिलाफ शिकायत करने से पहले सौ बार सोचेगा।

सरकार ने इस विवाद पर क्या दिया तर्क

प्रशासनिक निर्णयों की जटिलता : सरकार ने कहा कि हर दिन हजारों अधिकारी ऐसे फैसले लेते हैं जिनका असर करोड़ों लोगों पर पड़ता है. हर फैसला सभी को पसंद नहीं आता. अगर हर असंतुष्ट व्यक्ति एफआईआर कर देगा, तो प्रशासन पूरी तरह ठप हो जाएगा. नीति निर्धारण में जोखिमः सरकार ने कहा कि अधिकारी यदि हर समय यह सोचेंगे कि बाद में उन पर मुकदमा हो सकता है, तो वे कोई बड़ा निर्णय लेने से डरेंगे. इससे विकास की गति धीमी हो जाएगी. ईमानदार अधिकारियों का मनोबलः सरकार का कहना है कि धारा 17-A ईमानदार अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए जरूरी है, ताकि वे बिना डर के काम कर सकें. धारा 17 A का सीमित दायराः सरकार ने यह भी कहा कि यह कानून रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने वाले मामलों पर लागू नहीं होता. यानी रंगे हाथ पकड़े जाने पर तुरंत कार्रवाई हो सकती है।

एंटी करप्शन एक्ट की धारा 17-A पर S C के 2 जजों की अलग राय?

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने अलग-अलग राय दी है. इसी वजह से इसे स्प्लिट वर्डिक्ट कहा गया है।

यह कानून संविधान के मूल ढांचे के खिलाफः न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना- न्यायमूर्ति नागरत्ना ने साफ कहा कि यह कानून ईमानदार अधिकारियों की नहीं, बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों की रक्षा करता है. उनके अनुसार, जो अधिकारी ईमानदार है, उसे जांच से डरने की जरूरत नहीं होती. उन्होंने कहा कि यह कानून संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, क्योंकि यह कानून के सामने समानता के सिद्धांत को कमजोर करता है. उनका कहना था कि जांच करना पुलिस का अधिकार और कर्तव्य है. इस पर सरकार का नियंत्रण लोकतंत्र के लिए खतरनाक है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ऐसे प्रावधानों को रद्द कर चुका है, फिर भी उन्हें वापस लाया गया है।

कानून पूरी तरह खत्म करना सही नहीं: न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन- न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा कि भ्रष्टाचार रोकना भी जरूरी है और ईमानदार अधिकारियों को बचाना भी. उनके अनुसार, कानून को पूरी तरह खत्म करना सही नहीं होगा, बल्कि उसकी व्याख्या बदलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार की जगह लोकपाल या लोकायुक्त को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि जांच की अनुमति दी जाए या नहीं. उनका कहना था कि लोकपाल व्यवस्था पहले से मौजूद है, इसलिए उसी के जरिए जांच को छानना बेहतर होगा।

मामला बड़ी पीठ के पास क्यों भेजा गया?- जब सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश अलग-अलग राय देते हैं, तो मामला बड़ी पीठ के पास जाता है. अब यह पीठ तय करेगी कि कौन सा तर्क संविधान के अधिक अनुकूल है. इस फैसले के बाद तीन संभावनाएं बनती हैं।

पहला- धारा 17 A पूरी तरह रद्द की जा सकती है।

दूसरी- संशोधित रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

तीसरी- कोई नया संतुलित रास्ता निकाल सकता है।

ईडी को राहत, अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR स्थगित, ममता बनर्जी को नोटिस

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कोलकाता में चुनावी रणनीति बनाने वाली संस्था आईपैक पर ईडी की छापेमारी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप किए जाने संबंधी पूरे विवाद की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ममता बनर्जी और बंगाल सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई तीन फरवरी को करने की बात कही है. शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि घटना का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखा जाएगा. इसके साथ ही ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को अगली सुनवाई तक स्थगित रखने का आदेश दिया गया. ईडी ने अपने काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाया खटखटाया था. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस ममले पर जोरदार सुनवाई हुई. इससे पहले दोनों पक्षों की ओर से जमकर अपनी-अपनी दलीलें दी गई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि ईडी और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई में क्षेत्रीय पुलिस हस्तक्षेप कर

रही है. संविधान हरेक व्यवस्था को स्वतंत्र तरीके से काम करने की छूट देता है. ऐसे में एक राज्य की एजेंसी या पुलिस को इस तरह की गतिविधि करने की छूट नहीं दी जा सकती. साथ ही अदालत ने कहा कि स्थितियां और बिगड़ने और कानून का राज खत्म हो जाएगा. किसी भी केंद्रीय एजेंसी को किसी पार्टी के चुनावी कार्यक्रम में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है. लेकिन सही तरीके से किसी गैरकानूनी गतिविधि के खिलाफ एक्शन ले सकती है।

अगली सुनवाई 3 फरवरी को

मामले की अगली सुनवाई तीन फरवरी को होगी. इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस कमिश्नर, ष्ठतक्कको नोटिस जारी किया. इनसे दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा गया है. पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को सभी सीसीटीवी समेत अन्य डिवाइस व दस्तावेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है।

कपिल सिब्बल की दलील

बंगाल सरकार की ओर से जानेमाने वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि IPAC में कुछ भी नहीं था सिवाय चुनाव संबंधित दस्तावेजों के. इन कामों से ईडी का कोई संबंध नहीं है. कपिल सिब्बल ने कहा कि ममता बनर्जी, टीएमसी की अध्यक्ष होने के नाते, जेड कैटेगरी की सुरक्षा में हैं, इसलिए यह डीजीपी की जिम्मेदारी थी कि जब वह प्रतीक जैन के परिसर में प्रवेश करें, तो उनका साथ दें. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से कपिल सिब्बल व अन्य की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं. क्योंकि ईडी द्वारा लगातार चुनावों के पहले ऐसी कार्रवाई बार-बार कराई जाती है. कपिल सिब्बल के मुताबिक आई-पैक में चुनाव संबंधी दस्तावेज़ों के इतर कुछ नहीं था. इसका ईडी का कोई लेना देना नहीं था. यहीं नहीं ईडी की तरफ से क्षेत्रीय पुलिस को सूचित नहीं किया गया।

स्कूल को बताया मदरसा, पंचायत ने चला दिया बुलडोजर... बैतूल में मच गया हंगामा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मध्य प्रदेश के बैतूल में एक प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद से हंगामा मचा हुआ है. ढाबा गांव में बने इस स्कूल के भवन को लेकर ग्राम पंचायत की कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई है. लगभग 20 लाख रुपये की लागत से बनाए जा रहे इस भवन को बिना अनुमति निर्माण बताते हुए पंचायत द्वारा आंशिक रूप से गिराया गया. भवन निर्माण को लेकर गांव में मदरसा बनने की अफवाह भी फैली थी, जबकि भवन स्वामी ने स्कूल संचालन की अनुमति के लिए आवेदन किया हुआ है।

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक निर्माण को लेकर की गई पंचायत की कार्रवाई अब प्रशासनिक और राजनीतिक बहस का विषय बन गई है. ढाबा गांव में बनाए जा रहे एक स्कूल भवन को अवैध निर्माण मानते हुए ग्राम पंचायत ने उसका कुछ हिस्सा तोड़ दिया. भवन स्वामी का कहना है कि यह कदम नियमों की पूरी जानकारी न होने के कारण उठाया गया और इसे गलत तरीके की कार्रवाई बताया जा रहा है।

20 लाख हुए खर्च, कहां हुई चूक?

जानकारी के अनुसार, ढाबा गांव निवासी अब्दुल नईम द्वारा गांव के बच्चों को शिक्षा

सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक स्कूल भवन का निर्माण कराया जा रहा था, जिस पर लगभग 20 लाख रुपये खर्च किए गए. नईम का कहना है कि उन्होंने स्कूल संचालन के लिए संबंधित विभागों में आवेदन भी किया था, लेकिन निर्माण के दौरान ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी. इसी बीच गांव में यह चर्चा फैल गई कि यहां किसी धार्मिक संस्था से जुड़ा निर्माण किया जा रहा है. इस अफवाह के बाद मामला प्रशासन तक पहुंचा और ग्राम पंचायत ने इसे बिना अनुमति किया गया निर्माण मानते हुए पंचायत राज अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया. नोटिस और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंचायत द्वारा भवन का एक हिस्सा हटाने की कार्रवाई की गई. इस कदम से नाराज अब्दुल नईम ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा. उनके समर्थन में कांग्रेस नेता हेमंत बागडरें सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।

जुर्माना बनता है तो जमा करने के लिए तैयार

अब्दुल नईम का कहना है कि यदि नियमों के अनुसार कोई जुर्माना बनता है तो वह उसे जमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भवन को पूरी तरह तोड़ा जाना उचित नहीं है. उन्होंने प्रशासन से सहयोग और समाधान की अपील की है. इस मामले पर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने स्पष्ट किया कि ढाबा गांव का यह प्रकरण उनके संज्ञान में पहले से था. उन्होंने बताया कि यह निर्माण ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आता है और पंचायत राज अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई. कलेक्टर के अनुसार, नोटिस जारी करने और सुनवाई के बाद यह निर्माण नियमों के विपरीत पाया गया, जिसके चलते ग्राम पंचायत के माध्यम से संरचना हटाने की कार्रवाई की गई. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कदम किसी स्कूल, व्यक्ति या संस्था के विरोध में नहीं, बल्कि केवल नियमों के अनुपालन के लिए उठाया गया है. प्रशासन का कहना है कि भविष्य में यदि सभी आवश्यक अनुमतियां और नियमों का पालन किया जाता है, तो किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सकता है. फिलहाल यह मामला नियमों और प्रक्रियाओं के पालन को लेकर चर्चा में बना हुआ है।

संक्षिप्त ख़बरें

पूर्व सीएम अशोक गहलोत का आरोप- राजस्थान में साजिश के तहत कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम काटे गए

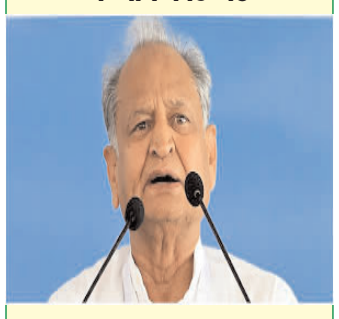

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि कुछ अनजान लोगों ने मतदाता सूची से कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा किए हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को इसे लेकर सतर्क रहने को भी कहा है। गहलोत ने कहा, ''मतदाता सूची के एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) में नाम कटवाने हेतु आपत्ति दर्ज करवाने का आज आखिरी दिन है। प्रदेशभर में कई स्थानों से ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि अनजान व्यक्तियों द्वारा बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए फॉर्म-7 जमा करवाए गए हैं।'' उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा,''मेरी कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं एवं बूथ स्तरीय अध्यक्षों से अपील है कि मुस्तैदी से इस पर नजर रखें एवं किसी भी वैध मत को न कटने दें।''

कांग्रेस नेता ने कहा, ''प्रशासनिक अधिकारियों से भी आग्रह है कि संविधान के अनुरूप काम करें, इस बौखलाहट से समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिन अब लदने वाले हैं। अगर आप गैरकानूनी काम करेंगे तो आपको भी किसी न किसी दिन कानून का सामना करना होगा।'

7.65 रुपए की चोरी, 50 साल से चल रहा था केस...अब मुंबई कोर्ट ने लिया ये बड़ा फैसला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मुंबई की एक कोर्ट ने 7.65 रुपए की चोरी के केस 1977 से चल रहा था. 50 साल बाद के बाद कोर्ट ने इस केस को बंद करने का डालने का निर्णय किया है. इस केस में दो अनजान आरोपी और एक शिकायत करने वाला शामिल था, जिनका पुलिस की दशकों की तलाश के बाद भी कोई पता नहीं चला. यह फैसला दशकों पुराने केस में हाल ही में आए कई फैसलों में से एक है, जो ठंडे बस्ते में पड़े थे और लीगल सिस्टम को जाम कर रहे थे. मझगांव कोर्ट ने 1977 के इस केस को पुराने केस को खत्म करने की अपनी कोशिश के तहत बंद कर दिया, जिनमें आरोपी या तो मर चुके थे, अनजान थे या उनका कोई पता नहीं चल रहा था।

1977 से चल रहा था 7.65 रुपए की चोरी का केस

1977 के इस चोरी के केस में दो अनजान लोगों पर 7.65 रुपए चोरी करने का आरोप था, जो पांच दशक पहले एक बड़ी रकम थी. हालांकि, नॉन-बेलेबल वारंट के बावजूद दोनों का पता नहीं चल सका, जिससे मामला ठंडे बस्ते में चला गया. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (मझगांव कोर्ट) आरती कुलकर्णी ने 14 जनवरी को यह कहते हुए केस बंद कर दिया कि मामला लगभग 50 साल पुराना है और 'बिना किसी प्रोग्रेस के बेवजह पेंडिंग' पड़ा हुआ है. कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा, 'बहुत ज्यादा समय लग गया है. मामले को पेंडिंग रखने का कोई मतलब नहीं है.' कोर्ट ने इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 379 (चोरी) के तहत पकड़े गए दो आरोपियों को बरी कर दिया और निर्देश दिया कि चोरी की गई 7.65 रुपये की रकम शिकायत करने वाले को लौटा दी जाए. कोर्ट ने ऑर्डर में कहा, 'अगर बताने वाला नहीं मिलता है, तो अपील पीरियड के बाद रकम सरकारी अकाउंट में जमा कर दी जाएगी।

कोर्ट ने केस बंद करने का किया फैसला

कोर्ट ने कहा कि चूंकि चोरी की गई रकम 2,000 रुपये से कम थी, इसलिए केस को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) के सेक्शन 260 के तहत समरी ट्रायल के लिए क्लासिफाई किया गया, जो छोटे अपराधों के लिए 'समरी ट्रायल' की इजाजत देता है, जिसमें चोरी भी शामिल है, जहां प्रॉपर्टी की कीमत कम होती है, ताकि जल्दी इंसाफ मिल सके. कोर्ट ने कहा कि इसी तरह, एक 30 साल पुराने मामले में, एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इंडियन पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत बुक किए गए एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि 1995 में चार्जशीट फाइल होने के बाद से उसका कोई पता नहीं चल रहा था।

2003 के एक रैश ड्राइविंग मामले में भी फैसला

2003 के एक रैश ड्राइविंग मामले में भी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ऐसा ही किया, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट ने कन्फर्म किया कि न केवल आरोपी, बल्कि असली जानकारी देने वाला और सभी गवाह भी अब ट्रेस नहीं हो पा रहे थे. आरोपी पर IPC के तहत सेक्शन 279 (रैश ड्राइविंग) और 338 (जान या पर्सनल सेफ्टी को खतरे में डालने वाले काम से गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत केस दर्ज किया गया था. कोर्ट ने कहा कि आरोपी के जल्द मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, और कहा कि फाइल को अनिश्चित काल तक खुला रखना गलत होगा।

विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भाजपा को प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन के लिए पांच नाम नहीं: कांग्रेस

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। सिन्हा ने कहा कि भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष का चयन किसी लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए नहीं, बल्कि नॉमिनेशन के माध्यम से किया गया है, लेकिन पार्टी में यह स्थिति बनी कि राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने वाले रघुबर दास, चंपई सोरेन अर्जुन मुंडा का नामांकन नहीं करना पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र के पूरी तरह समाप्त होने का स्पष्ट प्रमाण है। सिन्हा ने कहा कि भाजपा अब एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की 'पॉकेट संस्था' बनकर रह गई है। सिन्हा ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को पेसा कानून पर बोलने का कोई अधिकार नहीं क्योंकि अपने शासन काल में पेसा का 'प' नहीं लाने वाले भाजपा आज पेसा पर ज्ञान बांट रही है अभी नए- नए अध्यक्ष बने हैं अपने कमजोर और बिखरे संगठन पर ध्यान दे।

मुंबई सबकी है.... 'लात की बात' करने वाले राज ठाकरे को मिली ठोकर, बिहार के नेताओं ने बीएमसी चुनाव में गाड़ दिया झंडा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पटना- उत्तर भारतीयों के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी के लिए चर्चित रही राज ठाकरे की राजनीति को मुंबई के मतदाताओं ने सिरे से खारिज कर दिया. बीएमसी चुनाव में बिहार के कई नेताओं ने न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि निर्णायक जीत हासिल कर यह संदेश दिया कि मुंबई अब सबकी है. इस चुनाव में भाजपा और शिंदे शिवसेना गठबंधन को जो मजबूती मिली, उसमें प्रवासी मतदाताओं की भूमिका अहम रही. मुंबई के बीएमसी चुनाव में प्रवासी समुदाय खासकर बिहार के मिथिलांचल नेताओं का दबदबा साफ दिखा. बीएमसी यानी बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव के 227 वार्डों की लड़ाई में जहां महाराष्ट्र की राजनीति के चेहरे जैसे राज ठाकरे की पार्टी MNS अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई, वहीं बिहार और उत्तर भारत से आए नेताओं ने बड़ी जीत दर्ज की. इस चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों ने भी प्रमुख भूमिका निभाई, जिससे पारंपरिक शिवसेना-मीडिया कथन से अलग राजनीतिक रुख देखने को मिला है।

कांदिवली में शिव की हैट्रिक

कांदिवली पूर्व के वार्ड 23 से भाजपा के शिव कुमार झा ने भारी मतों के अंतर से जीत हासिल की और तीसरी बार जीत दर्ज कर हैट्रिक पूरी की. उन्होंने करीब 5,400 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को हराया जो इस क्षेत्र में उनके मजबूत प्रभाव को दिखाता है. यह जीत सिर्फ एक सीट की नहीं, बल्कि प्रवासी मतदाता शक्ति की पहचान के रूप में देखी जा रही है. छोटे से अंधराठाढ़ी ब्लॉक के गंगद्वार गांव से मुंबई तक अपनी राजनीतिक पहचान बनाने वाले शिव कुमार झा आज उत्तर भारतीय व मैथिल समुदाय के सशक्त चेहरे बने हैं. स्थानीय मतदाताओं की भारी हिस्सेदारी के कारण वे 'अपनों का नेता' के रूप में उभरे हैं. इन सभी नेताओं की जीत ने यह दिखाया कि मुंबई के पश्चिमी और पूर्वी उपनगरों में उत्तर भारतीय और मैथिल मतदाताओं की भूमिका निर्णायक रही है.वहीं, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS), जो बीएमसी जैसे महत्त्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में दमदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रही थी, इस चुनाव में अपेक्षानुसार परिणाम नहीं दे पाई. इससे स्पष्ट होता है कि मुंबई के विस्तार में अब केवल मराठी पहचान ही निर्णायक नहीं रह गई है, बल्कि विकास, कारोबार और प्रवासी मतदाताओं का समीकरण भी प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

बीजेपी-शिंदे शिवसेना गठबंधन की जीत

राज्य स्तर पर बीजेपी-शिंदे शिवसेना गठबंधन ने 114 से अधिक सीटों का बहुमत पार कर बीएमसी में नियंत्रण किया. भाजपा अकेले ही लगभग 89 वार्ड जीत रही है और उसके सहयोगी शिंदे शिवसेना ने भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी बनाई है. यह जीत पहले के 2017 के प्रदर्शन से बेहतर है और भाजपा-गठबंधन को मुंबई के राजनीतिक परिदृश्य में मजबूती देती है।

प्रवासियों की राजनीति और भविष्य की राह

राजनीति के जानकारों के अनुसार यह चुनाव सिर्फ पार्टियों का खेल नहीं रहा, बल्कि प्रवासी समुदाय विशेषकर बिहारियों की राजनीतिक उपस्थिति और पहचान की परीक्षा भी थी. उत्तर भारतीय मतदाता, जो मुंबई के कई इलाकों में संख्या में बढ़ता जा रहा है, उसने चुनाव परिणामों में निर्णायक भूमिका निभाई. इसके असर स्थानीय प्रशासनिक कामों से लेकर सामाजिक पहचान तक व्यापक स्तर पर दिखेंगे।

प्रवासियों ने तय की सत्ता की दिशा

मुंबई के बीएमसी चुनाव 2026 में बिहारियों की मजबूत भागीदारी और जीत ने यह संदेश दिया है कि अब महानगर की राजनीति में पारंपरिक मराठी पहचान के साथ-साथ प्रवासी समुदाय की शक्ति और भूमिका भी निर्णायक हो रही है. शिव कुमार झा की हैट्रिक और अन्य मिथिला नेताओं की जीत इस बदलाव की स्पष्ट मिसाल है।

स्मार्टफोन अब सुरक्षित कवचः नए नियम बदल देंगे सब कुछ

[कैसे भारत के स्मार्टफोन नियम बदलेंगे आपकी ऑनलाइन सुरक्षा]
[आपका फोन, आपकी प्राइवेसी: साइबर सिक्योरिटी का नया आयाम]

आज का युग पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है, और स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का सबसे अहम और व्यक्तिगत हिस्सा बन गया है। हम इसे सिर्फ बातचीत और मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कामकाज और सामाजिक जुड़ाव के लिए भी हर रोज इस्तेमाल करते हैं। यह छोटा उपकरण अब हमारी डिजिटल पहचान, वित्तीय लेन-देन और निजी जानकारी का मुख्य वाहक बन गया है। लेकिन इसी सहजता के पीछे छुपा है बड़ा खतरा। साइबर हमले, डेटा चोरी, फेक ऐप्स, मालवेयर और ऑनलाइन ठगी अब आम नागरिक की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। ऐसे में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित स्मार्टफोन साइबर सिक्योरिटी नियम न केवल समय की मांग हैं, बल्कि ये आम नागरिक की डिजिटल जिंदगी को सुरक्षित बनाने का एक निर्णायक कदम भी हैं। नए प्रस्तावों में सबसे पहला और अहम बदलाव है पूर्वस्थापित ऐप्स (ब्लोटवेयर) की स्वतंत्रता और यूजर कंट्रोल। अक्सर कंपनियां फोन में ऐसे ऐप्स इंस्टॉल कर देती हैं, जो बैकग्राउंड में कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन जैसी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच रखते हैं। यूजर को इसका पता तक नहीं चलता और यही रास्ता स्पाइवेयर और मालवेयर के लिए आसान बनता है। नए नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कोई भी ऐप यूजर की स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी डेटा तक पहुंच नहीं रख सकता। इसका सीधा फायदा यह होगा कि आम नागरिक अपनी प्राइवेसी और सुरक्षा पर खुद नियंत्रण रख सकेगा, और केवल उन्हीं ऐप्स का इस्तेमाल करेगा, जिन पर वह भरोसा करता है। सुरक्षा कवच को और मजबूत करने के लिए मालवेयर स्कैनिंग की अनिवार्यता भी प्रस्ताव में शामिल है। स्मार्टफोन अब नियमित रूप से और ऑटोमैटिक रूप से अपने सिस्टम को स्कैन करेगा, और किसी भी खतरनाक सॉफ्टवेयर का तुरंत अलर्ट देगा। साथ ही, सिस्टम लॉग्स को कम से कम 12 महीने तक डिवाइस पर स्टोर करना अनिवार्य होगा, ताकि साइबर अपराध की जाँच और ट्रेस करना आसान हो। इसका मतलब है कि फोन स्वयं एक सुरक्षा कवच बन जाएगा, और यूजर को अलग से किसी सुरक्षा ऐप पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। सॉफ्टवेयर अपडेट्स की प्रक्रिया में भी अब कड़ाई होगी। कंपनियों को बड़े अपडेट्स से पहले सरकार को सूचित करना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि अपडेट में कोई छुपी हुई सुरक्षा खामी या कमजोरियां न हों। अक्सर कंपनियां पुराने वर्जन पर छोड़ देती हैं, जिससे यूजर्स असुरक्षित रहते हैं। समय पर और सुरक्षित अपडेट्स से डेटा ब्रिच का खतरा कम होगा। आम नागरिक के लिए यह राहत की बात है, क्योंकि अधिकांश लोग अपडेट्स की अहमियत नहीं समझ पाते और पुराने वर्जन पर रहना उनके डेटा को जोखिम में डाल देता है। एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है सोर्स कोड शेयरिंग। सरकार कंपनियों से सुरक्षा जांच के लिए सोर्स कोड साझा करने पर विचार कर रही है। इससे टेस्ट लैब्स में सुरक्षा कमजोरियों और वल्नरेबिलिटी को जल्दी पकड़ा जा सकेगा। हालांकि कंपनियां इसे अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का खतरा मानती हैं।

आम नागरिक के नजरिए से यह कदम बेहद उपयोगी होगा क्योंकि इससे उनके डिवाइस की सुरक्षा बढ़ेगी, बशर्ते गोपनीयता और व्यापारिक रहस्य का संतुलन बना रहे। नए नियमों का मूल आधार डेटा प्राइवेसी है। यूजर की सहमति को अनिवार्य बनाया गया है। कोई भी ऐप बिना अनुमति के संवेदनशील डेटा नहीं ले सकेगा। यह डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के सिद्धांतों के अनुरूप है। आम नागरिक अब अपनी निजी जानकारी पर पूर्ण नियंत्रण महसूस करेगा। फेक ऐप्स और संदिग्ध लिंक्स के कारण डेटा चोरी की घटनाओं में कमी आएगी। इसके साथ ही, यह कदम ठगी, वित्तीय नुकसान और ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने में भी मदद करेगा। सख्त नियमों से साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी पर कड़ा नियंत्रण लगेगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है, जहां रोज लाखों लोग ऑनलाइन लेन-देन करते हैं। फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नई पाबंदियां कंपनियों को मजबूर करेंगी कि वे मजबूत सुरक्षा फीचर्स विकसित करें। इसका सीधा लाभ आम नागरिक को होगा–सुरक्षित बैंकिंग, भरोसेमंद ऐप्स और कम साइबर ठगी। हालांकि इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा। विशेषकर छोटी कंपनियों और स्टार्टअप्स पर यह अतिरिक्त बोझ डाल सकता है और कभी-कभी इनोवेशन की गति को प्रभावित कर सकता है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है–जनहित और डिजिटल सुरक्षा को सुनिश्चित करना। स्मार्टफोन अब केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि आम नागरिक का सुरक्षा साथी बन जाए। आम आदमी को भरोसा होना चाहिए कि उसका स्मार्टफोन उसका दोस्त है, दुश्मन नहीं। सख्ती जरूरी है, लेकिन पारदर्शिता, संतुलन और यूजर की सहमति के साथ। यदि ये नियम सही तरीके से लागू हो जाएं, तो करोड़ों भारतीयों की डिजिटल जिंदगी मजबूत, सुरक्षित और भरोसेमंद बन जाएगी। समय आ गया है कि हम साइबर दुनिया में सतर्क, जागरूक और सशक्त बनें, ताकि हमारी डिजिटल यात्रा सुरक्षित और निर्भय हो। इन नियमों के सफल और सही तरीके से लागू होने से केवल व्यक्तिगत डिजिटल सुरक्षा ही मजबूत नहीं होगी, बल्कि पूरे डिजिटल इकोसिस्टम का भरोसा भी और दृढ़ बन जाएगा। बैंकिंग, ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनेंगे। यूजर अब निश्चिंत रह सकेगा कि उसकी वित्तीय जानकारी, निजी डेटा और ऑनलाइन लेन-देन सुरक्षित हैं। यह कदम भारत को एक डिजिटल सुरक्षित और भरोसेमंद राष्ट्र बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा, जहां आम नागरिक की ऑनलाइन पहचान और व्यक्तिगत डेटा पर पूरा नियंत्रण रहेगा।

प्रो. आरके जैन

विश्व राजनीति का नया समीकरण, अमेरिका-ईरान और वेनेजुएला तनाव

आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक बहुआयामी संकट

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक राजनीति की धुरी को तेज़ी से बदल दिया है,उनके हाल के निर्णयों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, सैन्य रणनीति और कूटनीतिक संतुलन पर गंभीर प्रभाव डाला है जिन्हें व्यापक स्तर पर समझना अब वक्त की मांग है।

सबसे ताज़ा और व्यापक रूप से पुष्टि की गई घोषणा यह है कि ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर अमेरिका 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा वह आदेश 'तत्काल प्रभावी' और 'अंतिम व निर्णायक' बताया गया है। यह क़दम सीधे तौर पर उन देशों को निशाना बनाता है जिनके पास ईरान के साथ बड़े आर्थिक समझौते हैं, जैसे चीन, भारत, तुर्की, रूस और संयुक्त अरब अमीरात। इसके परिणामस्वरूप न केवल वैश्विक व्यापार संबंधों में विसंगति पैदा हो सकती है, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण अवरोध का सामना करना पड़ सकता है। टैरिफ नीति को व्यापारिक दबाव का एक हथियार बताया गया है, लेकिन यह अब स्पष्ट है कि यह उपाय परंपरागत प्रतिबंधों से आगे बढ़कर उपस्थित किया गया है – यह न केवल ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने का प्रयास है, बल्कि उसके व्यापारिक भागीदारों को भी अमेरिका के साथ रिश्तों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। इस क़दम से उस नेटवर्क पर असर पड़ेगा जो ईरान को कच्चे तेल, औद्योगिक कच्चा माल और कृषि वस्तुओं के रूप में समर्थन देता है, और भारत जैसे बड़े व्यापारिक राष्ट्रों को भी टैरिफ भार का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक संकट का विस्तार टैरिफ का कदम अंतरराष्ट्रीय बाजारों में दवाब बनाने की कोशिश है, लेकिन इससे वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखला में मूल्य वृद्धि, व्यापार विवाद और निवेश अनिश्चितता जैसी चुनौतियाँ उभर सकती हैं। उदाहरण के लिए, चीन खास तौर पर ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और उसके खिलाफ टैरिफ का असर न केवल तेल के व्यापार पर होगा बल्कि पूरे ईरानी लक्ज़मीन, वस्त्र और तकनीकी वस्तुओं के व्यापार को उलझा सकता है। इसके अलावा, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इससे अमेरिका-चीन व्यापार संबंधों पर तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि चीन पहले से ही पश्चिमी बाजार में अपने निर्यात पर भारी शुल्क का सामना कर रहा है। ऐसे में अतिरिक्त 25% टैरिफ से वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका बढ़ सकती है।

सैन्य रणनीति और तैयारी

आर्थिक दबाव के साथ-साथ, ट्रंप प्रशासन के कुछ सूत्र यह संकेत भी दे रहे हैं कि ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्पों पर विचार जारी है,खासकर उन स्थितियों में जहाँ ईरान के विरोध प्रदर्शन हिंसक दबाव में बदलते दिख रहे हैं। हालाँकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि अमेरिका ने सीधे ईरान पर हमला करने का निर्णय ले लिया है, सैन्य रणनीति के विकल्प 'तालिका में मौजूद' बताए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में यह भी उल्लेख है कि कतर जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी एयरबेस पर गतिविधियाँ बढ़ी हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि संभव सैन्य कार्रवाइयों के लिए तैयारी भी चल रही है, हालांकि इसकी पुष्टि स्वतंत्र स्रोतों द्वारा अभी सीमित रूप से ही हुई है।

ट्रम्प प्रशासन ने पिछले सालों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके ठिकानों पर कई प्रतिबंधात्मक उपायों और हमले जैसी कार्रवाइयों की भूमिका निभाई थी। इसी कड़ी में पिछले युद्धों और संघर्षों का हवाला देते हुए कई विश्लेषक मानते हैं कि संभावित भविष्य की सैन्य रणनीतियाँ भी गंभीर परिणाम लाने की क्षमता रखती हैं।कूटनीतिक परिदृश्य और प्रत्युत्तर कूटनीति के क्षेत्र में, ट्रंप प्रशासन की नीतियाँ स्वरूप में सख्त हैं लेकिन अपने साथ कई विरोध भी जड़ित करती हैं। उदाहरण के लिए, ईरान ने संवाद चैनल खुले रखने की इच्छा जताई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि तेहरान वार्ता के द्वार बंद नहीं करना चाहता है – बावजूद इसके कि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। चीन ने स्पष्ट रूप से अमेरिकी टैरिफ नीति का विरोध किया है, इसे 'अनैच्छिक, एकतरफा और अनिश्चितता पैदा करने वाला' बताया है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि टैरिफ युद्ध के समाधान के बजाय समस्या को और बढ़ाता है, और यह भी चेतावनी दी कि ऐसे उपाय 'कोई विजेता नहीं पैदा करते '। यूरोपीय और एशियाई देशों ने भी संकेत दिया है कि वे विवादास्पद फैसलों के संभावित स्थायी प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं, और ऐसे में वैश्विक स्तर पर कूटनीति, व्यापार संगठन और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों में व्यापक बहस की संभावनाएँ बन रही हैं।

वेनेजुएला प्रकरण से वैश्विक प्रतिक्रिया

ट्रम्प प्रशासन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाने का दावा किया, जिससे अंतरराष्ट्रीय क़ानून, संप्रभुता और शक्ति संतुलन पर तीखी बहस छिड़ गई है। कई देशों ने इसे वैश्विक हस्तक्षेप के रूप में देखा, और अमेरिका-विरोधी राष्ट्रों में चिंता और नाराज़गी बढ़ी है। यह कदम संकेत देता है कि अमेरिकी नीति अब केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही बल्कि औपनिवेशिक-जनित दबाव, सैन्य हस्तक्षेप और विरोधी राज्यों पर कड़ा रुख अपनाने की दिशा में अग्रसर है।

अमेरिका अगर सैन्य कदम उठता है, तो परिणाम मानवीय संकट, स्थानीय प्रतिरोध, ईंधन की कीमतों में वृद्धि, निवेश प्रवाह में गिरावट और वैश्विक सुरक्षा ढाँचे में तीव्र अस्थिरता हो सकते हैं। इसके अलावा, ईरान का उत्तरदायित्व, बातचीत के दरवाज़े खोलने की संभावना और स्थानीय प्रदर्शनकारी समूहों की भूमिका भी मध्य-पूर्व के भविष्य को आकार दे रहे हैं। ट्रंप प्रशासन की नीतियाँ, आर्थिक कठोरता, सैन्य विकल्पों की संभावना और कूटनीतिक तनाव ने वैश्विक शक्ति संतुलन को चुनौती दी है और एक ऐसे दौर की शुरुआत की है जहां अंतरराष्ट्रीय सहयोग और संघर्ष दोनों की लकीरें दिख रही हैं।

संजीव ठाकुर

मकरसंक्रांतिः अंधकार से प्रकाश, जड़ता से सक्रियता और स्वार्थ से सामूहिकता की यात्रा का पर्व

भारतीय पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते, बल्कि वे जीवन को प्रकृति और ब्रह्मांड से जोड़ने वाली सुव्यवस्थित जीवन-पद्धति हैं। मकरसंक्रांति इसका श्रेष्ठ उदाहरण है, जहाँ धर्म, विज्ञान, खगोल और जीवनशैली का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। यह वह कालखंड है जब प्रकृति, मनुष्य और समाज-तीनों एक साथ दिशा परिवर्तन करते हैं। इसी कारण इसे काल-परिवर्तन का पर्व भी कहा गया है।अंधकार से प्रकाश की यात्रा का स्पष्ट संकेत खगोल विज्ञान में मिलता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तरायण का आरंभ होता है। दिन बड़े होने लगते हैं और रात्रि का अंधकार क्रमशः कम होने लगता है। यह केवल भौतिक प्रकाश का विस्तार नहीं, बल्कि ज्ञान, आशा और सकारात्मकता का प्रतीकात्मक संदेश भी है। भारतीय मनीषा में सूर्य को मात्र खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि जीवन-ऊर्जा और चेतना का स्रोत माना गया है। जड़ता से सक्रियता की ओर बढ़ने का यह समय शरीर और मन,दोनों के लिए निर्णायक है। शीत ऋतु में बढ़ा आलस्य और निष्क्रियता मकरसंक्रांति के साथ समाप्त होने लगती है। सूर्य की ऊष्मा पुनः सक्रिय होकर शरीर में ऊर्जा का संचार करती है। इसी भावभूमि में पतंगबाजी, स्नान और खुले आकाश के नीचे सामूहिक गतिविधियाँ केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सक्रिय जीवनशैली के प्रतीक बन जाती हैं।

स्वार्थ से सामूहिकता की यात्रा इस पर्व की सबसे मानवीय विशेषता है। 'तिल-गुड़' का आदान-प्रदान केवल स्वाद का नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और मधुर संबंधों का संदेश है, जिसमें कड़वाहट छोड़कर मधुरता अपनाने का सांकेतिक आग्रह। दान की परंपरा समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने का माध्यम बनती है, जिससे सामाजिक संतुलन और समरसता बनी रहे।अतः मकरसंक्रांति हमें यह सिखाती है कि जैसे प्रकृति ऋतु परिवर्तन के साथ स्वयं को ढालती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपनी सोच, दृष्टि और आचरण में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहिए। आज जब समाज में अंधकार, जड़ता और स्वार्थ की प्रवृत्तियाँ प्रबल हो रही हैं, तब मकरसंक्रांति जैसे पर्व हमें स्मरण कराते हैं कि प्रकाश, सक्रियता और सामूहिकता ही सच्चे और सतत विकास का मार्ग हैं।

मनमोहन प्रकाश

हिंदी भाषी लोगों के अपमान पर सख्त हो - सरकार

अभी हाल में एक बार फिर महाराष्ट्र में बीएमसी चुनावों के अवसर पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने हिंदी भाषा को लेकर विवादित बयान दिया है । उन्होंने कहा कि यदि हिंदी भाषी लोग विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोग मराठी जनता पर हिंदी थोपने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें महाराष्ट्र से 'लात मारकर बाहर' कर दिया जाएगा । राज ठाकरे महाराष्ट्र की एक क्षेत्रीय पार्टी मनसे के प्रमुख हैं, जिनकी राजनीतिक हैसियत राज्य में सीमित रही है। इसके बावजूद वे समय-समय पर हिंदी भाषा और हिंदी भाषी नागरिकों के विरोध के माध्यम से मराठी अस्मिता को भड़काकर अपने राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास करते रहे हैं। महाराष्ट्र इस देश का अभिन्न अंग है और भारत का हर नागरिक इस राज्य में समान अधिकार रखता है। महाराष्ट्र किसी नेता या दल की बपौती नहीं है कि देश के नागरिक उसके डर या धमकी में रहें । जैसे भारतीय नागरिकों को देश में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है, वैसे ही उन्हें अपनी पसंद की भाषा बोलने का भी संवैधानिक अधिकार प्राप्त है । हिंदी देश की राजभाषा है और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी। कोई भी राजनेता चाहे वह राज ठाकरे ही क्यों न हो हिंदी बोलने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। राजनीतिक दबावों के चलते भले ही महाराष्ट्र सरकार ने तीसरी भाषा के मुद्दे पर समझौता किया हो, लेकिन हिंदी भाषी लोगों को 'लात मारकर निकालने' जैसे बयान पर राज्य सरकार को कठोर कदम उठाने ही चाहिए। माननीय न्यायालय से भी निवेदन है कि भाषा और जाति के आधार पर देश को बांटने वाले नेताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए उनकी राजनीतिक मान्यता पर पुनर्विचार किया जाए। महाराष्ट्र के मराठी नागरिक कभी भी भाषा या जाति के आधार पर विभाजन के पक्षधर नहीं रहे हैं। न महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों को सामान्यतः कोई समस्या रही है और न ही देश के अन्य हिस्सों में रह रहे मराठी भाई-बहनों को । वास्तविक समस्या उन क्षेत्रीय नेताओं को है, जिनका राजनीतिक अस्तित्व डगमगा रहा है और जो इसे बचाने के लिए समय-समय पर भाषा और क्षेत्रवाद का सहारा लेते हैं। आने वाला बीएमसी जनादेश ऐसे नेताओं को करारा जवाब देगा। बहरहाल, राज ठाकरे द्वारा हिंदी भाषी नागरिकों का अपमान करना न केवल निंदनीय है, बल्कि देश के भीतर देशवासियों को बांटने का अक्षम्य प्रयास भी है। अतः सरकार को उनके विरुद्ध सख्त और स्पष्ट कार्रवाई करनी ही चाहिए।

अरविंद रावल

संपादकीय

साबरमती से आसमान तक पतंगों की बोली में भारत-जर्मनी की दोस्ती की नई ऊँचाई

साबरमती रिवरफ्रंट से जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने एक साथ पतंग उड़ाई, तो वह दृश्य केवल उत्तरायण के उल्लास का प्रतीक नहीं था, बल्कि भारत-जर्मनी संबंधों की उस उड़ान का संकेत भी था, जो संस्कृति से लेकर रणनीति और व्यापार से लेकर तकनीक तक नए आयाम छू रही है। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव आईकेएफ-2026 का शुभारंभ एक ऐसे मंच पर हुआ, जहाँ रंगीन पतंगों के साथ-साथ कूटनीति, आर्थिक सहयोग और रक्षा साझेदारी के संदेश भी हवा में घुले हुए थे। अहमदाबाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पोल-हवेलियों की स्थापत्य झलक, पतंग संग्रहालय, संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियाँ इन सबने मिलकर यह बता दिया कि भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति के साथ वैश्विक मित्रताओं को कैसे सशक्त करता है। उत्तरायण गुजरात की आत्मा से जुड़ा पर्व है। यह केवल पतंगबाजी नहीं, बल्कि सामूहिक उत्सव, लोककला, संगीत और परंपरा का संगम है। जब इसी मंच पर जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, तो यह संदेश स्पष्ट था कि भारत अपने मित्र देशों को केवल औपचारिक बैठकों में नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक धड़कन में भी आमंत्रित करता है। पोल और हवेली की प्रतिकृतियाँ, कारीगरों द्वारा पतंग निर्माण का जीवंत प्रदर्शन, गरबा रास, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और मलखंब जैसी कलाओं की प्रस्तुतियाँ तथा भारतीय और जर्मन धुनों का समन्वय यह सब भारत की सॉफ्ट पावर का प्रभावशाली प्रदर्शन था। ऐसी सांस्कृतिक कूटनीति रिश्तों को केवल समझौतों तक सीमित नहीं रहने देती, बल्कि उनमें भावनात्मक मजबूती भी जोड़ती है। इसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बीच भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण अध्याय भी सामने आया। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को नई ऊँचाई देने वाली प्रोजेक्ट-75 की पनडुब्बी परियोजना इस साझेदारी का प्रतीक बनकर उभरी है। जर्मनी की प्रसिद्ध रक्षा कंपनी थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स और भारत के मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के बीच पहले से हुए समझौते के तहत छह अत्याधुनिक स्टील्थ पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण भारत में ही किया जाना प्रस्तावित है। लगभग 8 बिलियन डॉलर, यानी करीब 72 हजार करोड़ रुपये की यह डील भारतीय नौसेना के इतिहास की सबसे बड़ी परियोजनाओं में गिनी जा रही है। इन पनडुब्बियों की खासियत एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक है, जो उन्हें लंबे समय तक बिना सतह पर आए समुद्र के भीतर ऑपरेशन करने में सक्षम बनाएगी। कम शोर, अधिक स्टील्थ और लंबी अवधि तक छिपे रहने की क्षमता यही वह गुण हैं, जिनकी भारतीय नौसेना को लंबे समय से तलाश थी। इस डील का महत्व केवल सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं है। इसका सीधा लाभ 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानों को मिलता है। निर्माण भारत में होने से देश के रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी, कुशल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और तकनीकी ज्ञान का हस्तांतरण होगा। जर्मनी के लिए यह डील भारत जैसे बड़े और भरोसेमंद साझेदार के साथ दीर्घकालिक सहयोग का अवसर है, जबकि भारत के लिए यह समुद्री सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन को मजबूत करने का साधन बनती है। बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा और समुद्री चुनौतियों के दौर में यह साझेदारी भारत की प्रतिरोधक क्षमता को नई धार देती है। भारत और जर्मनी के रिश्ते केवल रक्षा तक सीमित नहीं हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग भी निरंतर विस्तार पा रहा है। आज भारत में दो हजार से अधिक जर्मन कंपनियाँ सक्रिय हैं, जो ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, रसायन, ऊर्जा, आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं। यह संख्या जर्मनी के भारत पर भरोसे और भारत के बढ़ते बाजार सामर्थ्य का प्रमाण है। द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो भारत और जर्मनी के बीच वार्षिक व्यापार लगभग 26 से 30 बिलियन डॉलर के बीच आंका जाता है, और आने वाले वर्षों में इसके और बढ़ने की संभावनाएँ जताई जा रही हैं। जर्मनी से भारत मुख्य रूप से मशीनरी, औद्योगिक उपकरण, ऑटोमोबाइल और उनके पुर्जे, रसायन, इलेक्ट्रिकल उपकरण, मेडिकल टेक्नोलॉजी और उन्नत इंजीनियरिंग उत्पाद आयात करता है। ये वे क्षेत्र हैं, जहाँ जर्मनी की तकनीकी दक्षता विश्वभर में प्रसिद्ध है। दूसरी ओर भारत जर्मनी को वस्त्र, परिधान, चमड़ा उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, आईटी सेवाएँ, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, कृषि-आधारित उत्पाद और इंजीनियरिंग गुड्स का निर्यात करता है। सेवा क्षेत्र में आईटी और डिजिटल समाधान भारत की मजबूत उपस्थिति को दर्शाते हैं, जबकि फार्मा और रसायन क्षेत्र भारत की विनिर्माण क्षमता का उदाहरण हैं। इस व्यापारिक रिश्ते का लाभ दोनों पक्षों को मिलता है। जर्मनी को भारत जैसे तेजी से बढ़ते बाजार तक पहुँच मिलती है, जहाँ युवा आबादी, बुनियादी ढांचे का विस्तार और औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएँ हैं। भारत को जर्मनी से उन्नत तकनीक, गुणवत्ता मानक और नवाचार का लाभ मिलता है, जो घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाता है। यही कारण है कि दोनों देश केवल पारंपरिक व्यापार तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि स्टार्टअप्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भी साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं। कच्छ-सौराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में निवेश और व्यापारिक सम्मेलनों के जरिए इस सहयोग को जमीनी स्तर तक ले जाने की कोशिश दिखाई देती है। बी-टू-बी और बी-टू-जी बैठकों में जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, वह बताता है कि स्थानीय उद्यमी, कारीगर, स्टार्टअप्स और तकनीकी विद्यार्थी वैश्विक अवसरों से जुड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे आयोजनों में उद्योग, कृषि, मत्स्य पालन, पर्यटन, पर्यावरण, सस्टेनेबिलिटी और भविष्य की तकनीकों पर संवाद न केवल निवेश को आकर्षित करता है, बल्कि ज्ञान और नवाचार के आदान-प्रदान को भी गति देता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की मुलाकात के बाद यह स्पष्ट संदेश सामने आया कि भारत-जर्मनी साझेदारी बहुआयामी है। यह साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों, नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और शांतिपूर्ण सहयोग पर आधारित है। रक्षा क्षेत्र में विश्वास, व्यापार में परस्पर लाभ, तकनीक में साझेदारी और संस्कृति में आत्मीयता इन चार स्तंभों पर यह रिश्ता आगे बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव जैसे मंच पर इसका प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि भारत अपनी कूटनीति को केवल बंद कमरों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे जन-उत्सवों और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाता है। साबरमती के आसमान में उड़ी पतंगें इस बात की गवाह बनीं कि भारत और जर्मनी के संबंध केवल कागजी समझौतों तक सीमित नहीं हैं। यह एक ऐसी मित्रता है, जो संगीत की लय, नृत्य की मुद्राओं, कारीगरों की कला और रणनीतिक समझौतों आदि सबमें समान रूप से दिखाई देती है। आने वाले वर्षों में जब यह साझेदारी और गहरी होगी, तब शायद इन पतंगों की डोरें नए व्यापारिक मार्गों, नई तकनीकी खोजों और मजबूत रणनीतिक संतुलन से जुड़ी नजर आएँगी। साबरमती से उठा यह दोस्ती का संदेश दूर-दूर तक गया है, और संकेत दे रहा है कि भारत-जर्मनी संबंधों का आकाश अभी और भी विस्तृत होने वाला है।

कांतिलाल मांडोत

माँ की गोद में बैठा बच्चा, स्क्रीन के साए में पला बचपन

[ममता, जो अब नोटिफिकेशन में बँट गई]
[डिजिटल परवरिश और टूटता भावनात्मक रिश्ता]

घर के भीतर सबसे गहरी खामोशी तब जन्म लेती है, जब माँ सामने होते हुए भी भीतर से अनुपस्थित होती है। बच्चा पास बैठा होता है, अपनी दुनिया खोलने को तैयार, पर माँ की आँखें किसी और चमकती दुनिया में भटकी रहती हैं। यह दूरी मीलों की नहीं, बस एक छोटी-सी स्क्रीन की है। यहीं से 'स्क्रीन माँ' का जन्म होता है। यह किसी पर आरोप नहीं, बल्कि हमारे समय की निर्विवाद सच्चाई है। डिजिटल रोशनी में पली यह परवरिश बाहर से आधुनिक लगती है, भीतर से भावनात्मक सूखे की ओर बढ़ती है। बच्चे सवाल नहीं करते, वे धीरे-धीरे चुप रहना सीख लेते हैं। डिजिटल समय ने माँ के जीवन के चारों ओर एक अदृश्य पिंजरा खड़ा कर दिया है। लगातार स्क्रॉल करना, तुरंत जवाब देना और हर पल साझा करना अब आदत नहीं, मजबूरी बन चुका है। माँ को लगता है वह बच्चे के पास है, पर सच यह है कि वह मानसिक रूप से अनुपस्थित रहती है। बच्चा बार-बार ध्यान खींचने की कोशिश करता है, पर हर बार हार जाता है। इसी हार में उसका आत्मविश्वास दरकने लगता है। स्क्रीन माँ के लिए लाइक और व्यूज़ प्राथमिक बन जाते हैं, जबकि बच्चे के लिए एक मुस्कान और एक नज़र ही सबसे बड़ा सहारा होती है। बच्चे का भावनात्मक संसार माँ की प्रतिक्रिया से आकार ग्रहण करता है। जब माँ तुरंत देखती, सुनती और समझती है, तब बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस करता है। स्क्रीन में डूबी माँ अनजाने में यह सुरक्षा छीन लेती है। बच्चा सीख लेता है कि उसकी बातों का इंतज़ार हो सकता है, भावनाएँ टाली जा सकती हैं। यही टलना आगे चलकर स्थायी चुप्पी में बदल जाता है। ऐसे बच्चे भीतर से बेचैन रहते हैं और बाहर से उदास दिखाई देते हैं। उनका विकास केवल शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी अधूरा रह जाता है। समस्या केवल फोन की नहीं, हमारी सोच और प्राथमिकताओं की है। समाज ने मातृत्व को भी एक प्रदर्शन में बदल दिया है। सुंदर तस्वीरें, आदर्श क्षण और परफेक्ट दिनचर्या का दबाव हर माँ पर हावी है। इस दौड़ में असली पल धीरे-धीरे खो जाते हैं। स्क्रीन माँ खुद को साबित करने में लगी रहती है, जबकि बच्चा सिर्फ स्वीकार्यता खोजता है। वह सीखता है कि दिखावा ज़्यादा महत्त्वपूर्ण है, सच्चाई कम। यही सीख धीरे-धीरे उसके रिश्तों में उतर जाती है और भावनात्मक ईमानदारी कमजोर पड़ने लगती है। घरों के छोटे-छोटे दृश्य इस बड़े संकट की असली तस्वीर सामने रखते हैं। भोजन की मेज़ पर फोन रखा है, खेल के समय कैमरा पहले चल पड़ता है, और सोते वक्त भी नोटिफिकेशन चुप नहीं होते। बच्चा गिरता है, संभलता है, पर माँ की नज़र देर से पड़ती है। यही देर बच्चे के मन में स्थायी निशान छोड़ देती है। वह खुद को कम महत्त्वपूर्ण समझने लगता है। असली माँ की मौजूदगी में बच्चा गलतियाँ करके भी सुरक्षित रहता है, जबकि स्क्रीन माँ के साथ वह धीरे-धीरे चुप रहना और सह लेना सीख जाता है। इस स्थिति का प्रभाव केवल क्षणिक नहीं, दूर तक जाने वाला है। ऐसे बच्चे अपनी भावनाएँ व्यक्त करने से डरने लगते हैं। वे या तो बेवजह आक्रामक हो जाते हैं या फिर पूरी तरह उदासीन। रिश्तों में जुड़ाव उन्हें कठिन लगने लगता है। माँ का स्पर्श, उसकी आवाज़ और उसका ध्यान उनके लिए भावनात्मक आधार होते हैं। जब यह आधार कमजोर पड़ता है, तो व्यक्तित्व भी डगमगाने लगता है। स्क्रीन माँ का असर सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि युवावस्था और वयस्क जीवन में भी रिश्तों की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। समाधान तकनीक को पूरी तरह छोड़ने में नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय करने में है। यदि माँ तय समय पर फोन से दूरी बना सके, तो बदलाव संभव है। दिन के कुछ घंटे केवल बच्चे के नाम हों, जहाँ कोई स्क्रीन बीच में न आए। बातचीत, खेल और साथ बैठना साधारण लगता है, पर असर असाधारण होता है। असली माँ बनने के लिए अतिरिक्त परिश्रम नहीं, बल्कि सजग और सच्ची उपस्थिति चाहिए, जो बच्चे को यह भरोसा दे कि वह सबसे पहले है। परिवार और समाज की भूमिका भी उतनी ही अहम है। यदि घर का वातावरण सहयोगी हो, तो माँ पर दबाव अपने आप कम हो जाता है। स्कूल और समुदाय यदि डिजिटल संतुलन पर खुलकर बात करें, तो जागरूकता बढ़ सकती है। तकनीक कंपनियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे लत को बढ़ावा न दें। बच्चों को भावनात्मक शिक्षा मिले, ताकि वे अपने मन और भावनाओं को समझ सकें। यह सामूहिक प्रयास ही स्क्रीन माँ की जगह संवेदनशील और उपस्थित माँ को वापस ला सकता है। यह सवाल केवल पालन-पोषण तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे भविष्य से जुड़ा है। माँ बच्चे की पहली शिक्षक होती है। यदि वही अनुपस्थित रहे, तो सीख अधूरी रह जाती है। भावनात्मक रूप से कमजोर पीढ़ी अंततः समाज को भी कमजोर बना देती है। फिर भी आशा शेष है। जब माँ एक पल ठहरकर बच्चे की ओर देखती है, तो टूटा हुआ संबंध फिर से जुड़ने लगता है। यही छोटा-सा ठहराव बड़े परिवर्तन की नींव बन सकता है। 'स्क्रीन माँ बनाम असली माँ' कोई टकराव नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी है। तकनीक उपयोगी हो सकती है, पर वह प्रेम का विकल्प कभी नहीं बन सकती। बच्चे को सबसे अधिक ज़रूरत माँ की आँखों की चमक, उसकी आवाज़ की गर्मी और उसकी बाहों की सुरक्षा की होती है। यदि माँ यह दे पाए, तो स्क्रीन अपने आप सीमित हो जाएगी। असली माँ की वापसी से ही भावनात्मक रूप से मजबूत बच्चे और संतुलित समाज का निर्माण संभव है।

कृति आरके जैन

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः**–उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.N.I NO. UPHIN/2009/34814 मो0 नं0 -9511151254, E-Mail :- news@swatantraprabhat .com

संक्षिप्त खबरें

मलिहाबाद के प्रधान 'कर्तव्य पथ' पर गणतंत्र दिवस परेड के बनेंगे साक्षी

मलिहाबाद। आगामी 26 जनवरी, 2026 को देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड में इस बार मलिहाबाद की धमक दिखाई देगी। विकास खंड मलिहाबाद की ग्राम पंचायत गोड़वा बरौकी के ग्राम प्रधान वीरेंद्र शुक्ल को केंद्र सरकार द्वारा विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारत सरकार की इस विशेष पहल के तहत देशभर के चुनिंदा पंचायत प्रमुखों को उनके जीवनसाथी के साथ राष्ट्रीय परेड देखने का अवसर दिया जा रहा है। इसी क्रम में वीरेंद्र शुक्ल को उनकी पत्नी कीर्ति शुक्ला के साथ आधिकारिक आमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है। वे कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली भव्य परेड सैन्य शक्ति के प्रदर्शन और सांस्कृतिक झांकियों को विशेष दीर्घा में बैठकर देखेंगे।पंचायत स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन और ग्रामीण विकास में सक्रिय भूमिका के चलते गोड़वा बरौकी के प्रधान का चयन इस सम्मान के लिए हुआ है। आमंत्रण पत्र मिलने के बाद से ही उनके शुभचिंतकों और ग्रामवासियों में हर्ष का माहौल है। प्रधान वीरेंद्र शुक्ल ने बताया यह केवल मेरा सम्मान नहीं बल्कि मेरी पूरी ग्राम पंचायत और मलिहाबाद क्षेत्र का सम्मान है। कर्तव्य पथ पर तिरंगे की आन-बान-शान का साक्षी बनना मेरे जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक होगा।

जंगल में लकड़ी लेने गए बुजुर्ग की संदिग्ध हालात में मौत, शव मिलने से मचा हड़कंप

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के झाबर हरदो पट्टी गांव निवासी एक बुजुर्ग का शव बुधवार सुबह जंगल में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान बसंत चमार (70) पुत्र शीतलदीन के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार बसंत चमार मंगलवार को नरेंद्रपुर की ओर जंगल में लकड़ी काटने गए थे, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं लौटे। इसके बाद परिवार और ग्रामीणों ने उनकी तलाश की, मगर कोई सुराग नहीं लग सका। बुधवार सुबह ग्रामीण जब खेतों की ओर गए तो जंगल में लकड़ी के गठ्ठर के पास बुजुर्ग का शव पड़ा मिला। शव के मुंह पर खून के धब्बे थे, हालांकि शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं पाए गए। शुरुआत में ग्रामीणों ने जंगली जानवर के हमले की आशंका जताई, लेकिन चोट के निशान न होने से मामला संदिग्ध माना जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी गंगादेई और बेटे रामशंकर व छेदीलाल का रो-रोकर बुरा हाल है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि शव सरेनी थाना क्षेत्र में मिला है। मामले की सूचना संबंधित थाने को दे दी गई है और आगे की जांच की जा रही है।

शीतला माता देवी मंदिर में हिंदू सम्मेलन का किया गया आयोजन

बिसवां/सीतापुर शीतला माता मंदिर परिसर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता समाजसेवी एवं प्रसिद्ध व्यवसायी लालता प्रसाद महादेव ने की। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित पूरन विभाग के सद्भाव प्रमुख, ने अपने संबोधन में समाज में एकता, सद्भाव और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि संगठित समाज ही सामाजिक समरसता और राष्ट्रहित को मजबूत करता है। संत समाज से अजय पुजारी शीतला माता मंदिर मंगरहिया बाजार, ने धार्मिक और नैतिक मूल्यों की महत्ता बताते हुए लोगों से आपसी भाईचारे और सदाचार के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। सम्मेलन में नंदकिशोर शास्त्री, विशाल गुप्ता, पीयूष मौर्य, अखिलेश चंद्र प्रकाश सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं अनुशासित वातावरण में संपन्न हुआ।

राशन के साथ कोटेदार जबरन थमा रहे हैं घटिया सामान

● प्रशासनिक अधिकारियों की शह पर खेला जा रहा भ्रष्टाचार और उपभोक्ताओं के शोषण का खेल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर :- सुमेरपुर क्षेत्र के राशन उपभोक्ताओं ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किये हैं।राशन कार्ड धारकों के मुताबिक स्थानीय राशन दुकानों पर उपभोक्ताओं से राशन के साथ सामग्री के नाम पर 100 रुपये प्रति कार्ड वसूले जा रहे हैं जिसमें पांच सामग्री का एक बंडल जबरन दिया जाता है ,जो घटिया गुणवत्ता का साबुन, वाशिंग पाउडर और खाद्य सामग्री के छोटे पैकेटों से भरा होता है, जिसकी कीमत बाजार में न के बराबर है। उपभोक्ताओं ने इसे खुला शोषण बताते हुए जिलाधिकारी और सदर विधायक से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

उपभोक्ताओं के अनुसार, हर राशन वितरण के दौरान विक्रेता एक वाशिंग साबुन, एक पैकेट वाशिंग पाउडर, एक छोटा पैकेट पास्ता, एक पैकेट मैकरोनी और एक पैकेट सेवई थमा देते हैं। इसके बदले 100 रुपये नकद ले लिए जाते हैं। 'यह सामग्री इतनी खराब है कि इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। कंपनी का नाम तक पता नहीं चलता,' बताती हैं राशन उपभोक्ता अमीन खान ने कहा, 'पूरे जनपद में वर्षों से कार्ड धारकों पर यह डाका चल रहा है। आपूर्ति विभाग की चुप्पी संदिग्ध है। दाल में काला तो है ही, खान का आरोप है कि यदि यह बंडल शासन के निर्देश पर जिला स्तर से आ रहा है, तो राशन की दुकानों के सूचना बोर्ड पर अन्य राशन वस्तुओं की तरह इसका नाम, मात्रा और कीमत क्यों नहीं लिखी जाती? बाजार में ऐसी सामग्री की कीमत 20-30 रुपये से ज्यादा नहीं, फिर 100 रुपये क्यों? कई कार्ड धारक बताते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवार इसे खरीदने को मजबूर हैं, क्योंकि विक्रेता राशन रोक लेते हैं। इससे न केवल आर्थिक नुकसान हो रहा, बल्कि स्वास्थ्य जोखिम भी बढ़ रहा है। क्षेत्रीय उपभोक्ताओं ने बताया कि यह समस्या सालों पुरानी है। पिछले साल भी इसी तरह के शिकायतें आई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 'गरीबों का खून चूसने का धंधा चल रहा है। आपूर्ति निरीक्षक आंखें बंद किए हैं दर्जनों कार्ड धारकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देने का फैसला किया है। उन्होंने मांग की है कि विक्रेताओं पर एफआईआर दर्ज हो, जांच टीम गठित हो और बंडल वसूली पर पूर्ण रोक लगे। सदर विधायक से भी अपील की गई है कि वे विधानसभा में मामला उठाएं। यदि शासन स्तर पर निर्देश हैं, तो उनकी प्रामाणिकता जांचे। उनका कहना है कि यह मामला सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। गरीबों को सस्ता अनाज देने का वादा करने वाली व्यवस्था में अगर ऐसी अनियमितताएं हैं, तो इसका व्यापक असर पड़ेगा।

मुस्तफाबाद बेलहनी में बनेगा अस्थायी हेलीपैड, ग्राम प्रधान अखिलेश यादव की पहल से विकास को नई गति

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रायबरेली। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुस्तफाबाद बेलहनी ग्राम पंचायत में विकास को लेकर एक और अहम कदम उठाया गया है। विकासखंड लालगंज के सक्रिय व युवा ग्राम प्रधान अखिलेश यादव की पहल पर ग्राम पंचायत में राजकीय अस्थायी हेलीपैड निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बीती 2 जनवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए गए थे कि समस्त विकासखंडों, तहसीलों एवं जनपद मुख्यालयों पर स्थायी एवं अस्थायी हेलीपैड निर्माण की कार्ययोजना शीघ्र उपलब्ध कराई जाए, जिससे आपातकालीन सेवाओं, प्रशासनिक कार्यों तथा वीआईपी मूवमेंट को सुचारु बनाया जा सके।

शासन के निर्देशों के क्रम में विकासखंड लालगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुस्तफाबाद बेलहनी में 50म50 वर्ग मीटर भूमि का चिन्हांकन किया गया है। चयनित भूमि गाटा संख्या 22 मि. 15.674 है, जो अभिलेखों में उसर दर्ज है। उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं है तथा हेलीपैड मानकों के अनुसार आसपास ऊंची इमारत, पेड़, बिजली का खंभा या टावर मौजूद नहीं है। सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए चयनित भूमि की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। हेलीपैड निर्माण की पहल से ग्रामवासियों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान अखिलेश यादव ने पंचायत को विकास के नए आयाम तक पहुंचाने का कार्य किया है, जिसकी सराहना क्षेत्र स्तर से लेकर उच्च स्तर तक हो रही है।

म़ो0 हसीन अंसारी ने डिजिटल लाइब्रेरी हेतु उपमुख्यमंत्री को पत्र देकर की मांग

लहरपुर सीतापुर नगर क्षेत्र के छात्र एवं छात्रों को प्रतियोगिकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बाहर न जाना पड़े उनके लिए नगर क्षेत्र में एक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद हसीन अंसारी ने उत्तर प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री माननीय बृजेश पाठक जी को एक पत्र देकर मांग कि है कि शीघ्र ही नगर क्षेत्र लहरपुर में एक सरकारी लाइब्रेरी की स्थापना की जाए जिससे नगर क्षेत्र के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बाहर न जाना पड़े और जो धन के अभाव के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उनको अपने क्षेत्र में ही तैयारी के अवसर मिल सकें। इस पर माननीय उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक जी ने आश्वासन दिया है अति शीघ्र ही एक लाइब्रेरी की स्थापना एवं लाइब्रेरी का सुंदरीकरण छात्रों को समर्पित की जाएगी।

व्यापारियों ने खिचड़ी भोज एवं सम्मान समारोह का किया आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

डलमऊ रायबरेली प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल इकाई डलमऊ के पदाधिकारी ने मकर संक्रांति के अवसर पर विशाल खिचड़ी भोज एवं व्यापारी सम्मान सभा का आयोजन किया जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने खिचड़ी का स्वाद चखा और आयोजित सभा में क्षेत्र के सम्मानित व्यापारियों एवं वरिष्ठ जनों को अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह एवं माला पहनकर सम्मानित किया गया 14 जनवरी को आयोजित हुए इस अवसर पर व्यापारियों द्वारा आयोजित सभा में रमाकांत अवस्थी द्वारा आल्हा गायन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया कार्यक्रम में व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम गुप्ता का जन्मोत्सव केक काटकर मनाया गया व्यापारियों ने उन्हें जन्मदिन की बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पंचायत अध्यक्ष डलमऊ ब्रजेश दत्त गौड़ उपस्थित रहे सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारी समाज का सहयोगी होता है व्यापारियों के हितों में यदि कहीं आंच तो वह प्रशासन से लेकर शासन तक की लड़ाई लड़ेंगे जिला अध्यक्ष दीप नारायण साहू ने कहा कि व्यापारियों की एकता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है वह व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे इस अवसर पर व्यापार मंडल के

संरक्षक योगेंद्र शुक्ला कोषाध्यक्ष सुशांत त्रिपाठी तहसील अध्यक्ष कुलदीप वैश्य ऋषभ गुप्ता कुलदीप साहू संतोष सोनकर सुधीर जायसवाल मनोज सोनकर लालजी सिंह राजू बलराम यादव त्रिलोकी सोनकर अशोक सोनकर एवं अन्य व्यापारी मौजूद रहे।

शौच के लिए गई युवती लापता

बिसवां (सीतापुर) थाना क्षेत्र बिसवां से एक युवती के रहस्यमय ढंग से लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की आशंका जताई है। मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र बिसवां के एक गांव की लगभग 25 वर्षीय युवती मंगलवार सुबह करीब सात बजे शौच के लिए गांव के बाहर स्थित सूखे तालाब की ओर गई थी। युवती अपने साथ मोबाइल फोन भी लेकर गई थी, लेकिन काफी देर बीतने के बाद भी वापस नहीं लौटी। परिजनों ने जब मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया तो फोन बंद मिला। परिजनों द्वारा आसपास के इलाकों और रिश्तेदारी में काफी तलाश की गई, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं लग सका। इसके बाद परिजन थाना बिसवां पहुंचे और मामले की लिखित तहरीर देकर पुलिस से गुमशुदगी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है तथा युवती की तलाश के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

एकीकृत कीट प्रबंधन द्वारा कम लागत में करें सरसों में माहू कीट का नियंत्रण

आजमगढ़ जनवरी माह बदलते तापमान के कारण सरसों की फसल को माहू नामक कीट से खतरा है. आजमगढ़ में 2025 में सरसों और रेपसीड की खेती का रकबा रिकॉर्ड 32000 हेक्टेयर तक पहुंच गया है. इस समय सरसों की फसल में फूल आ चुके है। तापमान परिवर्तन से सरसों की फसल पर माहू यानी एफिड से फसल को काफी नुकसान हो सकता है जिसके बचाव एवं निदान के लिए कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़-द्व के निर्देशन के कार्य कर रहे वैज्ञानिक डॉ विजय कुमार विमल ने बताया कि किसान भाई इनसे बचाव के लिए महंगे और जहरीले रसायनों का छिड़काव करते हैं। जिससे किसान भाई की लागत बढ़ जाती है। लागत कम करने के लिए किसान भाई कीटनाशकों के बजाय स्टिकी ट्रैप का उपयोग करके कम खर्च में फसलों को सुरक्षित कर सकते हैं.यह तकनीक कीटनाशकों के दुष्प्रभावों को कम करके पर्यावरण संरक्षण में मददगार साबित होगी। रसायनों के अधिकाधिक प्रयोग से लागत बढ़ने के साथ ये पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए स्टिकी ट्रैप आधुनिक तकनीक है. जिसमें पीले रंग कार्डबोर्ड की शीट होती है, जिस पर दोनों तरफ एक खास चिपचिपा पदार्थ लगा होता है जो माहू कीट को अपनी ओर आकर्षित करता है जिससे माहू कीट पीले रंग की ओर खिंचा चला आता है। और पीले कार्डबोर्ड पे लगे गोंद से चिपक कर मर जाते हैं। इस विधि से बिना किसी कीटनाशक के कीटों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है पीला स्टिकी ट्रैप बाजार ले सकते है या घर पे किसान भाई कम खर्च में बना सकते हैं, इसके लिए एक पीली पॉलीथीन शीट, पीला कार्डबोर्ड या कोई कार्डबोर्ड लेके पीले रंग से कलर कर दें(आकार 1 फीट × 1 फीट या इससे बड़ा)। इस पर दोनों तरफ अरंडी का तेल (कैस्टर ऑयल) या ग्रीस अच्छी तरह लगा दें। यह चिपचिपा होता है और कीटों को फंसाता है।

एक एकड़ सरसों की फसल में 15 से 20 पीले स्टिकी ट्रैप काफी होते हैं। स्टिकी ट्रैप को फसल के पौधों से 1-2 फीट ऊपर बांस या लकड़ी की छड़ी पर बांधें। हर 20-25 दिन में ट्रैप चेक करें। जब यह कीटों से पूरी तरह भर जाए तो नया ट्रैप लगा दें। ट्रैप को हमेशा फसल की ऊंचाई से थोड़ा ऊपर रखें, क्योंकि फसल बढ़ती रहती है। इस तरीके से कीटनाशकों पर होने वाला खर्च 70% तक कम हो सकता है। स्टिकी ट्रैप के साथ सरसों की फसल में माहू कीट के प्रकोप की स्थिति में नियंत्रण के लिए जैविक रूप से नीम का तेल का भी प्रयोग भी कर सकते हैं। नीम तेल तीन मिली प्रति लीटर में स्टीकर के साथ घोलकर छिड़काव करें।

जब अधिकता में माहू का प्रयोग हो तभी रासायनिक कीटनाशको का प्रयोग करें। रसायनिक नियंत्रण हेतु कीटनाशक थायक्लोप्रिड 21.7 प्रतिशत एससी या फिप्रोनिल पांच प्रतिशत एससी दवा का 0.5 मिली प्रति लीटर या ईमिडक्लरोप्रिड 17.8 एस एल 1 मिली. प्रति तीन लीटर पानी में स्टीकर या शैंपू घोलकर छिड़काव कर के माहू कीट का नियंत्रण कर सकते हैं।

मकर संक्रांति एकादशी पर खाटू श्याम मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

लालगंज (रायबरेली)। कस्बे के बरदाही मोहल्ला स्थित भगवान खाटू श्याम मंदिर में बुधवार को मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही मंदिर परिसर में आस्था और भक्ति का माहौल दिखाई दिया।श्रद्धालु कतार में लगकर विधि विधान से भगवान खाटू श्याम की पूजा-अर्चना की। सभी ने अपने परिवार और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर में महिला श्रद्धालुओं ने मंगल गीत गाए। भजनों की मधुर धुनों से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया। नगर के अलावा कई श्रद्धालु दूर दराज के गांवों से भी भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस वर्ष मकर संक्रांति और एकादशी एक साथ पड़ी है। ऐसा संयोग कई वर्षों बाद बना है। इसी कारण इस पर्व का धार्मिक महत्व और बढ़ गया है। साथ ही यह नववर्ष की पहली एकादशी भी है। इससे श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा गया। दिनभर मंदिर में दर्शन का क्रम चलता रहा। श्रद्धालुओं ने प्रसाद वितरित किया और भगवान से सर्व मंगल की प्रार्थना की।

एकल विद्यालय की खेलकूद प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाया दम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मलिहाबाद। स्थानीय गौशाला परिसर में एकल विद्यालय द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने कबड्डी, खो-खो, दौड़ और चित्रकला जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।कार्यक्रम में मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय संत महादेव बाबा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह जिला कार्यवाह अभय उपस्थित रहे। उनके साथ जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर पंकज, पतंजलि योगपीठ के रूपेश मिश्र और मलिहाबाद मंडल कार्यवाह वैभव गुप्ता ने भी शिरकत की।

खेलों के दौरान बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। संच प्रमुख लक्ष्मी पाल के नेतृत्व में सभी संच आचार्यों ने खेल आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराया। अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस तरह के ग्रामीण आयोजनों से

बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बल मिलता है।बुधवार को गोपेश्वर गौशाला पर एकल विद्यालय की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। नन्हे-मुन्ने खिलाड़ियों ने कबड्डी, खो-खो और दौड़ में अपना कौशल दिखाया वहीं चित्रकला के जरिए अपनी रचनात्मकता पेश की।इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों सहित समस्त संच आचार्य और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। मौके पर संच प्रमुख लक्ष्मी पाल और सभी आचार्यों की उपस्थिति में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

अलीनगर मोहल्ले में नलों से आ रहा दूषित पानी, लोग परेशान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 स्थित अलीनगर मोहल्ले में इन दिनों नलों से गंदा और बदबूदार पानी आने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीने योग्य पानी न मिलने के कारण मोहल्लेवासियों के रोजमर्रा के कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल निगम द्वारा सुबह और शाम पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन बीते कई दिनों से नलों से मटमैला और दुर्गंधयुक्त पानी निकल रहा है। यह पानी पीने तो दूर, घरेलू उपयोग के लायक भी नहीं है। मजबूरी में लोगों को बाहर से पानी लाना पड़ रहा है।

मोहल्ले की निवासी रेशमा बानो ने बताया कि गंदे पानी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक पाइपलाइन की मरम्मत नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि पानी में इतनी बदबू होती है कि बर्तन धोना और खाना बनाना तक मुश्किल हो गया है। वहीं परवीन बानो ने बताया कि मंगलवार की शाम हालात और भी खराब हो गए, जब नलों से बेहद गंदा पानी आने लगा। इससे पूरे घर का काम प्रभावित हुआ। उन्होंने आशंका जताई कि दूषित पानी के इस्तेमाल से बीमारियां फैल सकती हैं, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की सेहत को लेकर लोग चिंतित हैं।

मोहल्लेवासियों ने प्रशासन से साफ पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कराने और

पाइपलाइन की तत्काल जांच व मरम्मत कराने की मांग की है। इस संबंध में नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राजभान शुक्ला ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं था। उन्होंने कहा कि जानकारी मिलते ही टीम भेजकर जांच कराई जाएगी और जहां भी गड़बड़ी पाई जाएगी, उसे जल्द ठीक कराया जाएगा।

अन्नपूर्णा भवन के निर्माण के लिए किया गया भूमिपूजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महराजगंज रायबरेली। महराजगंज विकासखंड क्षेत्र के अलीपुर ग्राम पंचायत में बुधवार को अन्नपूर्णा भवन के निर्माण की शुरुआत हुई। पूर्ति निरीक्षक मुकेश पाण्डेय व ग्राम प्रधान सूरज कुमार ने सरकारी उचित दर की दुकान 'अन्नपूर्णा भवन' के निर्माण को भूमि पूजन कर शुरुआत की। अन्नपूर्णा भवन ग्रामीणों को लिए लाभकारी होगा। अन्नपूर्णा भवन के निर्माण के बाद ग्रामीणों को मिलने वाले सरकारी खाद्यान्न के अलावा आने वाले दिनों में सीएससी सेंटर सुविधा मिलने लगेगी। पूर्ति निरीक्षक मुकेश पाण्डेय ने बताया कि खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा लगभग साढ़े आठ लाख की लागत से अन्नपूर्णा भवन बनाया जा रहा है। जिसकी पहली किस्त में सवा चार लाख रूपये का बजट मिला है। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी

ग्राम पंचायत को दी गई है। निर्माण व्यय का पूरा विवरण ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव द्वारा रखा जाएगा। अन्नपूर्णा भवन में दो दुकानें बनेगी। एक दुकान में राशन का स्टोर होगा, वहीं दूसरी दुकान में वितरण का कार्य किया जाएगा। इस मौके पर शेत बहादुर सिंह, राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी, आनंद सिंह सुशील कुमार रतिभान मेड़ीलाल संतलाल कुंवरपाल राम सजीवन पंडित हरिश्चंद्र पांडेय गौरी शंकर मिश्रा दिवाकर पटेल आदर्श तिवारी आदि ग्रामवासी मौजूद रहे।

अनियंत्रित होकर ई रिक्शा पलटा, युवक दबकर घायल, गंभीर अवस्था में जिला रेफर

लालगंज (रायबरेली)। क्षेत्र के बेनीमाधवगंज गांव के निकट बुधवार को एक ई रिक्शा अचानक पलट गया। जिसके नीचे दबकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे फौरन इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। कपसरी गांव निवासी राम रतन ई रिक्शा पर सवार होकर जा रहे थे। तभी बेनीमाधवगंज गांव के निकट संतुलन बिगड़ने से ई-रिक्शा सड़क पर पलट गया। जिसके नीचे दबकर रामरतन गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदत से उन्हें फौरन उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दुर्घटना के बाद ई रिक्शा चालक रिक्शा लेकर मौके से फरार हो गया।

मुशायरे का किया गया आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवां (सीतापुर) शैखुल औलिया हज़रत गुलज़ार शाह रह0 अलैह के उर्स व मेले के मौके पर बिसवां में एक भव्य इंटरनेशनल मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें देश व विदेश से आए मशहूर शायरों ने शिरकत कर महफ़िल को यादगार बना दिया। मुशायरे की सदारत मास्टर तबस्सुम हुसैन कादरी ने की, जबकि संचालन शायर नदीम फरुख ने किया।

नदीम फरुख ने अपने शेर से मुशायरे का आग़ाज़ किया मेरी किस्मत कि ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। दुबई से आए शायर यासिर सिद्दीकी ने आपसी मतभेदों पर कटाक्ष करते हुए पढ़ा– दिन ही दिन था कि यहाँ रात कभी थी ही नहीं, हम में आपस में कोई बात कभी थी ही नहीं। कैसे फिर बीच में अपने ये तफिरका आया, हममें बंटने की रिवायत तो कभी थी ही नहीं।

नेपाल के शायर सरवर नेपाली ने अपने अनोखे अंदाज़ में पढ़ा– तुम काम नया देख लो कांधे के फरिश्तों, अहबाब हिसाबो किताब रखने लगे। जौहर कानपुरी ने देशभक्ति से ओतप्रोत शायरी पेश करते हुए कहा– न तजकिरा चूड़ियों का होगा न फ़िक्र सस्ती मिलेगी तुमको, तुम्हारे जौहर की शायरी में वतन परस्ती मिलेगी तुमको।

मशहूर शायरा शबीना अदीब ने सामाजिक संदेश देते हुए पढ़ा– अपना ग़म इस तरह थोड़ा कम कीजिये, दूसरों के लिए आँखे नम कीजिये, कुछ गरीबों के दिन भी संवर जायेंगे, आप अपनी ज़रूरत को कम कीजिये। अज़हर इक़बाल ने अपने भावपूर्ण शेरों से खूब वाहवाही बटोरी। उन्होंने पढ़ा– घुटन सी होने लगी उसके पास जाते हुए, मैं खुद रूठ गया हूँ उसे मनाते हुए।

आदिल रशीद ने मोहब्बत और सियासत पर तीखा शेर पढ़ा– इश्क़ चाहत की बात करते हैं, और नसीहत की बात करते हैं, तुम सियासत की बात करते हो, हम मोहब्बत की बात करते हैं। इल्मा हाशमी ने नई पीढ़ी की सोच को अपने अशआर में यूँ पिरोया- हर वसीले को ज़माने से जुदा रखते सोचते हैं, हम नई नस्ल के बच्चे हैं नया सोचते हैं।

हिमांशी बाबरा ने दर्द भरे अंदाज़ में पढ़ा– रोज़ की बेबसी से हार गये, सूरमा दिल्लगी से हार गये, आप जो थे तो हौसला था मुझे, आप क्यों ज़िंदगी से हार गए। तबरेज़ मुनव्वर राना ने अपने शेर से महफ़िल में जोश भर दिया– ऐसा नहीं है कि मेरे मुक़ाबिल नहीं हैं

आप, बस सामने से जंग में शामिल नहीं हैं आप। सतलज राहत इन्दौरी ने अपनी खास शैली में पढ़ा– एक दिन ये कमाल हो ही गया, सबसे रिश्ता बहाल हो ही गया, जो मेरे क़त्ल की फ़िराक़ में था, उसका भी इंतकाल हो ही गया। इसके अलावा अल्ताफ ज़िया, हाशिम फिरोजाबादी, शरीफ भारती और शाइस्ता सना ने भी अपना कलाम पेश कर दर्शकों से भरपूर दाद हासिल की।

इस मौके पर मेला अध्यक्ष अब्दुल मसर्रत अली, सेक्रेटरी सैय्यद हुसैन कादरी, कार्यवाहक अध्यक्ष महबूब अली, मुशायरा संयोजक डॉ. अहमद अली अंसारी, हबीबुल्ला ख़ां, एजाज़ अली, आराध्य शुक्ला, विवेक कुमार पाण्डेय, हस्सान रज़ा, रेहान कादरी, अन्नू, नुसरत अली समेत बड़ी संख्या में शायरी प्रेमी मौजूद रहे। मुशायरा देर रात तक चला और साहित्यिक प्रेमियों के लिए यादगार बन गया।

बरेसर पुलिस ने क्षेत्र में हो रही चोरी का किया खुलासा एक नाबालिग व उसके साथी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

गाजीपुर। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को बरेसर पुलिस ने एक नाबालिग व उसके साथी को गिरफ्तार कर क्षेत्र में हुई कुछ चोरी की घटनाओं का खुलासा किया है । पुलिस ने बताया की गिरफ्तार किये गये आरोपियों के पास से चोरी के समान सहित एक तमंचा व एक कारतुश भी बरामद हुआ है। आरोपियों के गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए थाना प्रभारी ने बताया की थाने की एक टीम उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार पाण्डेय के देखरेख में क्षेत्र में भ्रमणशील थी तभी मुखबिर से सूचना प्रदान हुई की अलवालपुर में जो चोरी हुई है। उसमें शामिल दो लोग जहुराबाद पोखरी पर मौजूद हैं। सूचना मिलते ही हमने क्षेत्र में भ्रमणशील टीम को मुखबिर द्वारा बताए गए उक्त स्थान के लिए रवाना कर दिया। जहां से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर थाने लाया गया जब दोनों अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया की साहब अलावलपुर में जो चोरी की घटना हुई थी वो हम लोगों द्वारा ही की गई थी । पुलिस ने बताया की इन पकड़े गये अभियुक्तों के निशान देही पर एक ठेला, लोहे का आंगन, व बाईस सौ रुपये को भी बरामद किया पुलिस ने बताया की चोरी के समान के अलावा एक अवैध तमंचा व एक कारतूस भी बरामद हुआ है। जो इनके पास ही मौजूद था। पकड़े गये अभियुक्त विशाल उर्फ धनजीत राम उम्र 28 वर्ष जो अलावलपुर स्थानीय थाने का ही निवासी वहीं दुसरा विकास कुमार राम जो मात्र अभी 15 वर्ष का ही नाबालिग है। इन दोनों ने ही मिलकर क्षेत्र में चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। अब इनके उपर निम्न धाराओं के तहत एक को जेल व नाबालिग विकास कुमार को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। इन दोनों को पकड़ने वाली टीम में उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार पाण्डेय, कां अरविंद पांडेय,कां राकेश कुमार मोर्य, कां संतोष कुमार मोर्य, चालक कांस्टेबल चंदन,कां महेश कुमार आदि शामिल थे।

संक्षिप्त खबरें

बुढ़ार जन परिषद की एक बैठक

शहडोल अध्यक्ष श्री सुखदीप खरे के निवास पर संपन्न हुई बैठक में प्रमुख रूप से श्रीमती सुरसारि मिश्रा अध्यक्ष महिला प्रकाश द्वार फिरदौस खान को उपाध्यक्ष महिला प्रवक्ता सुश्री सुमन सेन को सचिव महिला प्रकोष्ठ और श्रीमती राजकुमारी सिंह को सह सचिव पद पर नियुक्त किया जाने की अनुशासन श्री अरुण प्रकाश गुप्ता को पदोन्नति कर कार्य के अनुसार, अध्यक्ष और श्री संजय श्रीवास्तव को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नई नियुक्ति दी गई, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर साकार्य भागीदारी निभाने को कहा गया कार्यक्रम के अंत में श्री बी.पी.तिवारी जिन्हे पत्रकार संघ का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है उनको मार्ल्यापण कर बधाई दी गई तथा श्री पवन मिश्रा को सचिव पद से नियुक्ति पत्र दिया गया।

दो अरब में मंडल की सड़कों का होगा नवीनीकरण

हमीरपुर:- लोक निर्माण विभाग ने अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में चित्रकूट धाम बांदा मंडल के चारों जनपदों की 334 सड़कों के नवीनीकरण करने के लिए 20043.30 लाख की कार्य योजना भेजी है, जिसमें 1378.38 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का नवीनीकरण कराया जाएगा।हमीरपुर जनपद में 7140.85 लाख, महोबा ने 2455.92 लाख, बांदा ने 7611.58 लाख एवं चित्रकूट ने 2834.95 लाख की कार्य योजना भेजी गई है।लोक निर्माण विभाग में पांच वर्ष से अधिक पुरानी सड़कों का नवीनीकरण कराने की योजना संचालित है। जिसके चलते प्रति वर्ष चक्र में आने वाली सभी सड़कों का नवीनीकरण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाता है। इसी क्रम में आगामी वित्तीय वर्ष 2026 व 27 में पांच वर्ष के नवीनीकरण चक्र में आने वाली सड़कों का नवीनीकरण कराने के लिए कार्य योजना लखनऊ मुख्यालय स्तर से मांगी गई थी। जिस पर चित्रकूट धाम बांदा मंडल से दो अरब 43 लाख 30 हजार की कार्य योजना भेजी गई है। जिसमें जनपद बांदा में प्रांतीय खंड बांदा द्वारा 60 मार्गो की लंबाई 175.22 किलोमीटर में नवीनीकरण कार्य के लिए 23 करोड़ 32 लाख 86 हजार की कार्य योजना भेजी गई है। जबकि जनपद महोबा में प्रांतीय खंड महोबा द्वारा 24 सड़कों की लंबाई 88.52 किलोमीटर लागत 10 करोड़ 51 लाख 13 हजार एवं निर्माण खंड एक महोबा ने 35 सड़कों की लंबाई 104.65 किलोमीटर लागत 14 करोड़ 04 लाख 79 हजार तथा जनपद हमीरपुर में प्रांतीय खंड हमीरपुर ने 11 सड़कों की लंबाई 110.42 किलोमीटर लागत 17 करोड़ 85 लाख 17 हजार एवं निर्माण खंड दो हमीरपुर ने 326.59 किलोमीटर लागत 53 करोड़ 55 लाख 68 हजार की कार्य योजना भेजी है। इस प्रकार बांदा मंडल की कुल 334 सड़कों की लंबाई 1378.38 किलोमीटर का नवीनीकरण करने के लिए 20043.30 लाख की कार्य योजना भेजी गई है। स्वीकृति जल्द ही मिलने की संभावना है।

सिसोलर ने खम्हरिया को एक विकेट से हराकर जीती ट्रॉफी

हमीरपुर:- मौदहा विकास खण्ड सिसोलर गांव में बुधवार को क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान सिसोलर टीम ने मेहमान टीम खम्हरिया को एक विकेट से हराकर ट्राफी पर कब्जा कर लिया। सिसोलर गांव में बीती 30 दिसंबर से क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ था। इसमें सिसोलर गुसियारी, भैसमरी, बिहरका, भटुरी, अतरैया, छिमौली, मुंडेरा, पढ़ोरी, टोला माफ, पिपरौंदा, मेहुना, भैंसरा, सांड़ी, भमौरा और खम्हरिया की टीमों ने हिस्सा लिया।बुधवार को इस टूर्नामेंट फाइनल मैच मेजबान सिसोलर और खम्हरिया टीमों के बीच खेला गया है। जिसमें खम्हरिया की टीम ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवरों में 100 रन बनाए इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी सिसोलर टीम ने अपने पंद्रहवें ओवर की आखिरी गेंद में एक विकेट से टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला जीत लिया है।मैच के मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान विजय शंकर प्रजापति ने विजेता टीम को ट्राफी देकर सम्मानित किया है।मैन ऑफ़ द मैच और मैन ऑफ़ द सीरीज सरवन सिंह चंदेल रहे हैं।अंगद प्रजापति और विनय यादव ने अम्पायर की भूमिका निभाई है। वहीं टूर्नामेंट के आयोजक राहुल चंदेल, सरवन चंदेल, धीरज, मनीष, हिमांशु सिंह, जीतू मौर्या सहित अन्य लोगों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों और अतिथियों का आभार प्रकट किया है।

प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम विवाद: प्रशासन ने डॉ अंबेडकर प्रतिमा हटवाई, रखवाई गई थाने में

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कोंच(जालौन)- नदीगांव थाना क्षेत्र के ग्राम घिलौर के मजरा गांव ईश्वरी में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम को लेकर सामने आए विवाद के बाद प्रशासन ने मंगलवार की देर रात आयोजकों के विरोध को दरकिनार कर मौके से प्रतिमा हटवा दी है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने फिलहाल उक्त प्रतिमा थाने में पुलिस की सुपुर्दगी में रखवा दी है।

बिना प्रशासनिक अनुमति के प्रतिमा स्थापित किए जाने और प्रस्तावित अनावरण व शोभायात्रा से पहले कुछ ग्रामीणों द्वारा विरोध जताए जाने के बाद प्रशासन ने कार्यक्रम पर रोक लगा दी थी। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल के साथ पीएसी भी तैनात कर दी गई थी।

कुछ दिन पूर्व ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक में गांव की परती भूमि पर डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए चयनित भूमि पर 20 दिसंबर से चबूतरा बनना शुरू कर दिया गया था और चबूतरा बन जाने के बाद चबूतरे पर प्रतिमा भी रख दी गई थी। पहले अनावरण कार्यक्रम 1 जनवरी को आयोजित करने की योजना थी लेकिन तैयारियों में विलंब होने पर इसे गत रोज मंगलवार को आयोजित करने की तैयारी थी। प्रधान द्वारा 8 जनवरी को उपजिलाधिकारी कार्यालय में प्रतिमा अनावरण एवं शोभायात्रा की अनुमति के लिए आवेदन भी किया गया था। हालांकि, कार्यक्रम से एक दिन पहले सोमवार रात कुछ ग्रामीणों ने प्रतिमा स्थापना और अनावरण कार्यक्रम का विरोध करते हुए उच्चाधिकारियों से शिकायत कर दी थी। मंगलवार सुबह गांव में तनावपूर्ण हालात बन गए थे। सूचना मिलने पर एसडीएम ज्योति सिंह, क्षेत्राधिकारी परमेश्वर प्रसाद व थानाध्यक्ष शशिकांत चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे और स्थिति का जायजा लिया था। प्रशासन ने बिना अनुमति के प्रतिमा स्थापित किए जाने को नियम विरुद्ध बताते हुए अनावरण कार्यक्रम पर रोक लगा दी थी। इसी दौरान कार्यक्रम आयोजक प्रधान पक्ष एवं भीम आर्मी से जुड़े लोग कार्यक्रम करने पर जोर देते रहे। प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझाकर प्रतिमा हटाने का प्रयास किया था, लेकिन मौके पर मौजूद लोग इसके लिए तैयार नहीं हुए थे। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए एहतियातन पीएसी बल तैनात कर दिया गया था। देर रात प्रशासन ने प्रतिमा मौके से हटवा कर थाने में पुलिस की सुपुर्दगी में रखवा दी है। क्षेत्राधिकारी परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि बिना अनुमति के प्रतिमा स्थापित की गई है। फिलहाल प्रतिमा को हटवा दिया गया है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, पुलिस बल पैनी नजर बनाए हुए है। प्रशासनिक अनुमति मिलने के बाद ही प्रतिमा रखने की अनुमति दी जाएगी।

ब्यौहारी बुढार और उमरिया में स्त्री रोग विशेषज्ञ की होगी भर्ती उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल

● जिला अस्पतालों में फारेसिक विशेषज्ञ नियुक्ति होंगे

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
दिनेश चौधरी की रिपोर्ट

शहडोल से बुढार। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंगलवार को भोपाल में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जहां उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए की जिला अस्पतालों में फारेसिक विशेषज्ञ की नियुक्ति करें। ब्यौहारी बुढार और उमरिया में स्त्री रोग विशेषज्ञ रिक्त पदों की जल्द भर्ती करें। उन्होंने नर्सिंग टीचर्स के 59 राजपत्रित पदों की मांग लोक आयोग को भेजने के लिए कहा है। सिंगरौली नर्सिंग कॉलेज के लिए भूमि चिन्हित कर समय सीमा में टेंडर सक्रिय को पूरा करने के निर्देश दिए। अस्पताल में स्वास्थ्य उपकरणों को उपलब्ध सुनिश्चित करें शुक्ला ने चिकित्सा को की पदोन्नति के लिए लोक सेवा पदोन्नति नियम से छूट देने संबंधित कार्यवाही सम्मान प्रशासन विभाग के जरिए करने के निर्देश दिए चिकित्सा महाविद्यालयों में आउटसोर्स पदों की स्वीकृति के मानकों में सुधार कर स्किल्ड सेमी स्किल्ड कर्मियों का प्रावधान करने के लिए कहा गया यह प्रस्ताव मंत्री परिषद में लाया जाएगा नवीन चिकित्सा महाविद्यालय में रिक्त ट्यूटर डेमोंस्ट्रेटर पदों पर सीधी भर्ती के निर्देश दिए हैं।

भाजपा सरकार पर जनता की आवाज दबाने का आरोप, कांग्रेस व एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन

देवरिया। प्रदेश की भाजपा सरकार पर जनता की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस व एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष विजय शेखर मल्ल 'रोशन' के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में वाराणसी में एनएसयूआई के शांतिपूर्ण आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की गई। उन्होंने कहा कि एसआईआर, वोट चोरी और मनरेगा को कमजोर किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और हिरासत लोकतंत्र पर हमला है। जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी सहित कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस का अमानवीय व्यवहार भाजपा सरकार की घबराहट को दर्शाता है। कांग्रेस नेताओं ने इसे तानाशाही रवैया बताते हुए कहा कि सरकार असहमति की आवाज से डर रही है। प्रदर्शन में पूर्व जिलाध्यक्ष राघवेन्द्र सिंह, जयदीप त्रिपाठी, मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी, सत्य प्रताप अंशु सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस व एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

ऐसे आयोजनों से बढ़ता है आपसी सौहार्द- एडीएम

● सामाजिक जिम्मेवारी निभाने में पत्रकारों का है अहम योगदान- विधायक

मकर संक्रांति पर्व पर भाईचारा की भावना होती है मजबूत- मनोज राजा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कदौरा(जालौन)- कस्बे के मेला प्रांगण में मकर संक्रांति पर्व के मौके पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब इकाई कदौरा एवं नगर पंचायत अध्यक्ष रविकांत शिवहरे द्वारा संयुक्त रूप से सामाजिक समरसता और सेवा भाव के तहत खिचड़ी भोज व कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कस्बे के तमाम लोगों ने खिचड़ी भोज का आनंद लिया। वहीं करीब दो सैकड़ा जरूरतमंदों को सर्दी से राहत हेतु कंबल भी वितरित किए गए।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी संजय कुमार एवं विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय विधायक विनोद चतुर्वेदी, नगर पंचायत अध्यक्ष रविकांत शिवहरे, उपजिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी ए.के. सिंह, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के जिलाध्यक्ष और दैनिक जागरण झांसी के जिला ब्यूरो चीफ मनोज राजा रहे। अन्य अतिथियों में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अजहर बेग, वरिष्ठ पत्रकार आबिद नकवी, अलीम सिद्दीकी, विनय गुप्ता, आशीष शिवहरे, अजय श्रीवास्तव, प्रदीप महतवानी, थाना प्रभारी प्रभात कुमार सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मौजूद कस्बावासियों के बीच अपने संबोधन में अपर जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे सामाजिक आयोजनों से आपसी एकता और सौहार्द बढ़ता है। मकर संक्रांति पर्व पर खिचड़ी का दान सनातन धर्म में अत्यंत पुण्य का कार्य माना जाता है। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब व नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा आयोजित कार्यक्रम निश्चित रूप से सराहनीय है। विधायक विनोद चतुर्वेदी ने कहा कि पत्रकार केवल खबरें लिखने तक सीमित नहीं होते हैं, बल्कि समाज को जोड़ने और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला सच्चे अर्थो में पत्रकार कहलाता है। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के जिलाध्यक्ष मनोज राजा ने कहा कि संगठन की नगर इकाई द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम प्रशंसनीय है। इस तरह के कार्यक्रम समय-समय पर होते रहने चाहिए जिससे समाज में आपसी भाईचारा और सहयोग की भावना मजबूत होती है। नगर पंचायत अध्यक्ष ने भी मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब नगर इकाई अध्यक्ष राजेश गुप्ता पिंटू, विकास कुमार सिंह, नवनीत मिश्रा, राजा विश्वकर्मा, आफताब अहमद, शरीफ खान, गंभीर गौतम, राहुल परिहार, राजन सेंगर, चांद खान, अफजाल अहमद, फैसल खान, शशांक शुक्ला, अमित गुप्ता, अभिषेक कुमार, पवन विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे।

वेटेरन्स दिवस पर वीर नारियों का सम्मान, डीएम ने शहीदों के बलिदान को किया नमन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उरई(जालौन)- 10वें वेटेरन्स दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद सैनिकों की वीर नारियों को सम्मानित कर राष्ट्र की कृतज्ञता व्यक्त की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने वीर नारियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित करते हुए अंगवस्त्र, श्रीफल, मिठाई एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए तथा शहीद सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

जिलाधिकारी ने कहा कि देश की सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी वीर नारियां धैर्य, साहस और आत्मबल की प्रतीक हैं, जिनका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन शहीद परिवारों के सम्मान और सहयोग के लिए सदैव संवेदनशील और प्रतिबद्ध है। सम्मानित की गई वीर नारियों में सिपाही स्वर्गीय राजवीर सिंह (ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1984) की पत्नी उमा देवी, गार्ड्समैन स्वर्गीय तिलक सिंह (ऑपरेशन मेघदूत, 1988) की पत्नी श्याम बाई, नायक स्वर्गीय अरविंद सिंह (ऑपरेशन पवन, 1989) की पत्नी राधा देवी, नायक स्वर्गीय सरदार सिंह (ऑपरेशन रक्षक, 1995) की पत्नी हेमलता, हवलदार स्वर्गीय सरमन सिंह (ऑपरेशन कारगिल, 1999) की पत्नी सरोज कुमारी, सिपाही स्वर्गीय योगेन्द्र सिंह पाल (ऑपरेशन रक्षक, 1999) की पत्नी भूरी देवी, शहीद हवलदार धर्मपाल सिंह राजपूत (ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, 2020) की पत्नी क्रान्ती देवी तथा शहीद नायक मनोज

कुमार सिंह (ऑपरेशन रक्षक, शहादत 11 मार्च 2004) की पत्नी पुष्पलता शामिल रहीं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने वीर नारियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए शहीदों के बलिदान को नमन किया। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा आदि अधिकारी मौजूद रहे।

वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन पर हुई शोभा सभा

हमीरपुर:- मौदहा बार एसोसिएशन में लम्बा समय देने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन पर एक शोकसभा आयोजित की गई। मौदहा बार संघ सहित न्यायलय के कामों में अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखण्ड बिताने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता पिपरौंदा निवासी अजय सिंह सेंगर के निधन पर मौदहा बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्तताओं ने बार संघ के मीटिंग हाल में एक शोकसभा आयोजित कर दो मिनट का मौन धारण किया और मृतक आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उसके बाद भारी संख्या में अधिवक्ताओं ने उनके निवास पर पहुंच कर मृतक अधिवक्ता के परिवार को सांत्वना दी और उनके दुख में भाग लिया। इस दौरान अधिवक्ता उमाशंकर त्रिपाठी, साकेत त्रिपाठी, ब्रजकिशोर त्रिवेदी, उमेश नामदेव, वीरेंद्र प्रजापति, विजय सिंह यादव, महेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद रजा सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।

आकाशीगंगा में मकर संक्रांति के पवित्र स्नान के लिए आधी रात से ही भक्तों का उमड़ी भीड़

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

धेमाजी असम। असम-अरुणाचल सीमांत के लिकाबली के आकाशीगंगा में मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर गंगा स्वान के लिए मध्य रात से श्रद्धालुओं ने बीड़ करते हुए दिखाई दिए। असम-अरुणाचल और देश के दूसरे हिस्सों से कई संत, साधुओ ने डेरा लगाई है। लिकाबली-आलो रोड पर सात किलोमीटर दूर में है ऐतिहासिक शिव मंदिर। मंदिर के बगल से 850 सीढ़ियाँ उतरकर पहुँचा जाता है आकाशीगंगा में। सदियों से पहाड़ से वहती झरने की किनारे भक्तों ने आस्था और बिस्वास की पवित्र गंगा स्वान करते हुए आ रही हैं।

लोगों का मानना है कि इस दिव्य गंगा में नहाने से ज़िंदगी भर के जाने-अनजाने कारणों से हुए कई पाप मिट जाते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो इस मान्यता को मानते हैं और आज भी शिव मंदिर में आकाशी गंगा में नहाने और अपने और अपने परिवार की भलाई की कामना करने आते हैं। गैरतलब है कि लिकाबली प्रशासन ने मकर संक्रांति से तीन दिनों के लिए इंटर-स्टेट पासपोर्ट में ढील दी है। इस साल, स्थानीय प्रशासन ने आकाशी गंगा में कोई एंट्री फीस नहीं ली है।

स्व. कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में अखिल भारतीय विधायक गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का रंगारंग आगाज़, पहले मुकाबले में रोमांचक मुकाबला

● कोरिया ने बुढार को एक रन से हराकर क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

शहडोल बुढार। स्थानीय स्व.कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में मंगलवार को अखिल भारतीय विधायक गोल्ड लैदर बाल क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य उद्घाटन हुआ। देश के विभिन्न राज्यों से आई 10 टीमों की भागीदारी वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह खेलप्रेमियों और गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। उद्घाटन के साथ ही टूर्नामेंट का पहला मुकाबला भी खेला गया, जिसने दर्शकों को रोमांच से भर दिया।

उद्घाटन समारोह में दिखा उत्साह

उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉ.केदार सिंह रहे, कार्यक्रम की अध्यक्षता धनपुरी नगर पालिका की अध्यक्षा श्रीमती रविंदर कौर छाबड़ा ने की जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर परिषद बुढार की अध्यक्षा शालिनी सरावगी एवं बकहो नगर परिषद की अध्यक्षा मौसमी केवट रहीं अतिथियों के रूप में हनुमान खंडेलवाल, वैभव विक्रम सिंह, शेखर चौधरी, राकेश पांडे, दौलत मनवानी, संतोष लोहानी, रिलायंस फाउंडेशन से अजीत सिंह कामता गौतम, पीके भगत, युनुस खान आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिले के कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने कहा कि ऐसे टूर्नामेंट युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का सशक्त माध्यम हैं और खेल भावना को मजबूत करते हैं।

फ्रेंड्स क्लब बुढार के अध्यक्ष श्री कैलाश विशनानी ने अपने स्वागत भाषण में बताया कि टूर्नामेंट नॉकआउट आधार पर खेला जाएगा और फाइनल मुकाबला आगामी 21जनवरी को होगा। विजेता और उपविजेता टीमों को आकर्षक ट्रॉफी और नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जबकि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, गेंदबाज और मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए भी विशेष पुरस्कार रखे गए हैं, टूर्नामेंट के संयोजक जैतपुर विधानसभा के विधायक जयसिंह मरावी ने बताया कि पूरे आयोजन के पीछे का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना एवं अन्य प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए एक उचित मंच प्रदान करना है।

पहला मुकाबला बना दर्शकों के लिए यादगार

उद्घाटन के बाद टूर्नामेंट का पहला मैच डीसीए कोरिया और बुढार टीमों के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोरिया की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में टीम ने द्व7विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज घनश्याम ने शानदार 75 रन की पारी खेली, जबकि बल्लेबाज पवन ने तेजी से32 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। विपक्षी टीम की ओर से गेंदबाज पीयूष ने 3 विकेट झटके।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी बुढार टीम ने आक्रामक शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज रितेश ने 38 गेंदों में 70 रन बनाकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया। अंतिम ओवरों में दर्शकों की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन सधी हुई गेंदबाजी के दम पर कोरिया टीम ने मैच द्व1 रन से अपने नाम कर लिया। मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार घनश्याम को दिया गया। यह पुरस्कार बुढार के लोकअभियोजक आलोक राय ने प्रदान किया, बुढार टीम के प्रायोजक वैभव विक्रम सिंह जबकि कोरिया टीम के प्रायोजक जगन्नाथ शर्मा रहे। मैच में अंपायरिंग आनंद त्रिपाठी और नृपेंद्र सिंह ने की, जबकि मैच काआंखों देखा हाल कलाम मोहम्मद, अजय द्विवेदी और सुधीर शर्मा ने सुनाया।

खेल प्रेमियों में उत्साह

उद्घाटन मैच को देखने के लिए बड़ी संख्या में खेलप्रेमी स्टेडियम पहुंचे। दर्शकों ने खिलाड़ियों का तालियों और नारों के साथ उत्साहवर्धन किया। आयोजकों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुकाबले और भी रोमांचक होंगे और युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर अवसर मिलेगा। अखिल भारतीय लैदर बाल क्रिकेट टूर्नामेंट का यह शुभारंभ स्थानीय खेल संस्कृति को नई ऊर्जा देने के साथ-साथ क्षेत्र के उभरते क्रिकेटरों के लिए एक मजबूत मंच साबित होता नजर आ रहा है।

आयोजन में उनकी है प्रमुख भूमिका

यह पूरा आयोजन बुढार नगर की खेल एवं सामाजिक संस्था फ्रेंड्स स्पोर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी के तत्वाधान में किया जा रहा है संस्था के अध्यक्ष कैलाश विशनानी और संस्था के सदस्य अनिल सोनी, श्रीनिवास द्विवेदी, पवन नियर्सेस, अवधेश पांडे (पिंटू), राजीव त्रिपाठी, महेंद्र त्रिपाठी, राकेश त्रिपाठी पत्रकार दिनेश चौधरी पत्रकार शिवम कुशवाहा पत्रकार जुगुल मिश्रा इनकी उपस्थित उल्लेखनी रही इत्यादि के देखरेख में खेला जा रहा है।

सपा सांसद पर खंगार जाति का अपमान करने का आरोप, आक्रोशित समाज ने सौंपा ज्ञापन

उरई (जालौन)- जालौन- गरौठा-भोगनीपुर के सांसद नारायण दास अहिरवार पर आरोप है कि उन्होंने खंगार जाति को अछूत शब्द से अपमानित किया। इसको लेकर खंगार जाति के लोगों ने सांसद के खिलाफ ज्ञापन देते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने सांसद के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र का है। यहां पर जालौन-गरौठा-भोगनीपुर के सांसद नारायण दास के बयान को लेकर खंगार जाति के लोगों में भारी आक्रोश है। इसी को लेकर समाज के लोगों ने दर्जनों की संख्या में एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी करते हुए सांसद के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। खंगार क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष सुभाष उदय पिंडारी का कहना है कि सांसद नारायण दास द्वारा जो शब्द कहे गए हैं वो समाज को अपमानित करने वाले हैं। उन्होंने संपूर्ण खंगार समाज को अपमानित किया है। सासंद के खिलाफ लोकसभा में कार्यवाही हो अन्यथा समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा।

दिल्ली में भाजपा पूर्वांचल कार्य लय में मकर संक्रांति पर भव्य आयोजन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी देश वासियों को बधाई

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
बादल हुसैन

नई दिल्ली, कुल कुल मौसम और उत्सवी माहौल, के बीच राजधानी दिल्ली में भाजपा कार्यालय में पूर्वांचल मोर्चा के द्वारा आयोजित लोहड़ी मकर ।संक्रांति का पर्व पूरे पारंपरिक उत्साह और सांस्कृतिक रंग के साथ पतंगबाजी, तिल- गूड के पकवान और दान -पुणय के साथ धुमधाम से मनाया गया। मकर संक्रांति के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष विरेंद्र सचदेवा, और भाजपा के सभी नेता, कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोगो के साथश्र दिल्ली के भाजपा प्रदेश कार्यालय में लोहड़ी मकर संक्रांति के त्योहार का आनंद उठाया। और एक दुसरे को लोहड़ी मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर रंग बिरंगी पतंग उड़ाकर आसमान को रंगीन बना दिया।इस एतिहासिक आयोजित कार्यक्रम का साक्षी बने सैकडों लोगों ने इस पारंपरिक उत्साह को सराहना की । इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने । बताया कि मसर संक्रांति के अवसर तिल खाने एवं खिलाने का विषेश महत्त्व है। लोहड़ी मुख्य रूप से एक कृषि एवं सांस्कृतिक पर्व है, जो सर्दियों के अंत,रबी फसलों की कटाई के आगमन तथा सूर्य देव और अग्नि देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है, इस अवसर पर मुग़ल काल के वीर नायक दुल्ला भट्टी को भी स्मरण किया गया, जिन्होंने अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष कर गरीबों की सहायता की। वही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा की यह पर्व समुदाय में एकजुटता, सामाजिक समरसता और नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है।

मोबाइल की लत पड़ी भारी, युवक का मानसिक संतुलन बिगड़ा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर:- मोबाइल फोन का अत्यधिक प्रयोग और घंटों तक लगातार ऑनलाइन गेमिंग एक 20 वर्षीय युवक को भारी पड़ गया।राठ कस्बा के सिकंदरपुरा निवासी अमृतलाल का अधिक मोबाइल फोन के प्रयोग से मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। परिजनों के अनुसार युवक पिछले कुछ दिनों से अजीब हरकतें करने लगा था और बिना वजह लगातार गीत गुनगुनाता रहता था। स्थिति बिगड़ने पर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (छ्राष्ट) राठ लेकर पहुंचे। छ्राष्ट में मौजूद चिकित्सकों ने प्रारंभिक जांच में युवक के एंजायटी (चिंता विकार) से ग्रसित और नींद पूरी न होने की आशंका जताई है। डॉक्टरों का कहना है कि लंबे समय तक स्क्रीन पर रहने, नींद की कमी और मानसिक दबाव के कारण युवाओं में इस तरह की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। यह मामला युवाओं में बढ़ते डिजिटल एडिक्शन पर एक गंभीर चेतावनी है। विशेषज्ञों के अनुसार मोबाइल और गेमिंग का संतुलित उपयोग, समय पर नींद,

शारीरिक गतिविधि और पारिवारिक संवाद बेहद जरूरी है, ताकि मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके। यह सच्ची घटना अभिभावकों और युवाओं दोनों के लिए सोचने का विषय है कि तकनीक का उपयोग सुविधा के लिए हो, न कि मानसिक बीमारी की वजह बने।